04 - लैंगिक समानता की ओर न्यायपालिका का आत्ममंथन

05 - बदलाव का उजास, हमारी जाति गरीबी है

A Daily News Magazine
भोपाल
मंगलवार, 24 फरवरी, 2026
भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित
वर्ष 23, अंक 174, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2
सुबह सवेरे

06 - अनुशासन, निरंतर एकाग्रता से तैयारी और आत्मविश्वास को मूल...

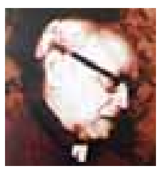

07 - जिल्दसाज

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

देश में तकनीक के जरिए मातृभाषाओं को बचाने की जरूरत

उमेश चतुर्वेदी

तकनीकी दौर में मातृभाषाएं सबसे ज्यादा संकट में हैं। इसकी वजह यह है कि मातृभाषाओं को बोलना भी तकनीक से प्रभावित हो रहा है और लेखन तो पूरी तरह उसी पर निर्भर हो गया है। तकनीक की खासियत कहें या कमी, वह बाजार के लिहाज से खुद को विकसित करती है और अपने उत्पादों के लिए इसी नजरिए से शोध करती है। चूंकि मातृभाषाओं में कई ऐसी हैं, जिन्हें बोलने या जिनका इस्तेमाल करने वालों की संख्या बेहद कम है, इसलिए उनसे कमाई की संभावना कम है। चूंकि तकनीकी विकास में काफी धन लगता है, और मातृभाषाओं के एक हिस्से से कमाई की गुंजाइश नहीं दिखती, इसलिए तकनीक उनके सहज इस्तेमाल में दिलचस्पी नहीं दिखाती। इसलिए मातृभाषाओं की बड़ी संख्या लुप्त होने के कगार पर हैं। भारत को ही देखिए। साल 1961 की जनगणना के आंकड़ों के लिहाज से भारत में 1652 भाषाएं थीं। लेकिन सिर्फ दस साल बाद यानी 1971 में यह संख्या घटकर महज 808 रह गई। ऐसा बदलाव तब हुआ, जब तकनीक का बोलबाला नहीं था। लेकिन अब बात उससे भी आगे बढ़ चुकी है। 2013 के भारतीय लोकभाषा सर्वेक्षण के अनुसार, विगत 50 वर्षों में 220 भाषाएँ जहां लुप्त हो गई हैं, वहीं 197 भाषाएँ खत्म होने की कगार पर हैं।

मातृभाषाओं के लुप्त होने की कई अन्य वजहें भी हैं। भाषाशास्त्रियों के मुताबिक, व्यक्तिवादी दर्शन, उपभोक्तावाद, सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों में आ रहे बदलाव, और शहरीकरण के साथ ही पारंपरिक मूल्यों के प्रति घटती निष्ठा और रोजगार के साधनों के रूप में भाषाओं की घटती संख्या भी मातृभाषाओं के खात्मे की वजह बना है। इसके बावजूद कुछ अपवादों को छोड़ दें तो मातृभाषाओं को लेकर कुछ इलाकों में सम्मोहन बरकरार है। शायद यही वजह है कि इस बार के अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के लिए यूनेस्को ने जो थीम रखी है, वह बेहद अहम जान पड़ती है। यह थीम है, 'भाषाओं का महत्वः रजत जयंती और सतत विकास'। इस थीम का ध्येय वाक्य 'अनेक भाषाएँ, एक भविष्य' है। पूर्वी बंगाल में 1952 में शहीद हुए भाषा आंदोलनकारियों की याद में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की शुरूआत की पिछले साल यानी 2025 में रजत जयंती थी। तब यूनेस्को ने इस दिवस को भाषाई विविधता, डिजिटल सशक्तिकरण और समावेशी शिक्षा के माध्यम से सतत विकास पर जोर देने पर केंद्रित किया था।

इस बार के ध्येय वाक्य से साफ है कि यूनेस्को चाहता है कि विश्व के सतत विकास में मातृभाषाओं की महत्ता को रेखांकित किया जाए। मातृभाषाएं एक तरह से भाषायी लोकतंत्र को रचती हैं। इस लोकतंत्र को बचाए बिना विविधरंगी संसार को नहीं बचाया जा सकता। सोचिए, अगर उपभोक्तावाद, व्यक्तिवाद और तकनीकी वर्चस्व की वजह से एक रस और एक भाषायी संसार तैयार हो जाए तो दुनिया कितनी नीरस होगी, ज्ञान के तमाम स्रोत तब या तो सूख चुके होंगे या फिर भुला दिए गए होंगे। इसलिए मातृभाषाओं को बचाना और उन्हें सांस्कृतिक लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में जिंदा रखना जरूरी हो जाता है।

यूनेस्को की ओर से घोषित 'भाषाओं का महत्व - रजत जयंती और सतत विकास' विषय, एक तरह से भाषायी विविधता, बहुभाषावाद और सतत विकास के बीच गहरे संबंधों को ही रेखांकित करता है। चूंकि यूनेस्को ने मातृभाषाओं को संरक्षित करने, भाषायी विविधता को जिंदा रखने और उन पर रश्क करने के साथ ही शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए प्रयासरत है, इसलिए वह लगातार भाषाओं को बचाने का संदेश दे रहा है। दुनिया में इन संदेशों को सुना और समझा भी जा रहा है। चूंकि भाषाएँ सिर्फ संवाद का साधन ही नहीं होतीं, बल्कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने का अहम औजार भी हैं, लिहाजा प्राथमिक शिक्षा में उन पर जोर दिया जा रहा है। 2020 में आई भारत की नई शिक्षा नीति में भी मातृभाषाओं में शिक्षा-विशेषकर प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। दुनियाभर के शिक्षाशास्त्री मानते हैं कि मातृभाषा आधारित शिक्षा समावेशी होती है और बच्चों की समझ को बेहतर बनाने में मददगार होती है। इतना ही नहीं, इसके चलते बच्चे की सीखने की प्रक्रिया भी तेज होती है। मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा के भी नतीजे बेहतर होते हैं। चूंकि सतत विकास में शिक्षा का स्थान अहम है और मातृभाषा आधारित शिक्षा बेहतरीन होती है, यही वजह है कि सतत विकास के लक्ष्यों को अब मातृभाषा के जरिए मिलने वाली शिक्षा में गंभीरता से खोजा जा रहा है। इसीलिए दुनिया एक बार फिर मातृभाषाओं के जरिए शिक्षा की ओर उन्मुख होती दिख रही है।

जैसे-जैसे अधिकाधिक भाषाएँ विलुप्त होती जा रही हैं, भाषायी विविधता खतरे में पड़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, विश्व की 40 प्रतिशत आबादी को उस भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल रहा है, जिन्हें वे बोलते या समझते हैं। मातृभाषाओं का संरक्षण इसलिए भी जरूरी है कि स्थानीय समाज उनके जरिए शिक्षा हासिल कर सकें।

मातृभाषा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सांस्कृतिक पहचान और बौद्धिक नींव की आधारशिला है। यह सोचने, समझने और संवाद करने का सबसे सहज माध्यम है, जो बच्चे को उसकी विरासत से जोड़ती है। मातृभाषा में शिक्षा से आत्मविश्वास बढ़ता है, संज्ञानात्मक कौशल विकसित होते हैं, और दूसरी भाषाएं सीखना आसान हो जाता है।

मातृभाषा में शिक्षा से बच्चे की अवधारणाओं को समझने की क्षमता तेज होती है और रचनात्मकता बढ़ती है। मातृभाषा संस्कृति, परंपराओं और इतिहास को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का मुख्य माध्यम है। व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को मातृभाषा में सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सकता है, जिससे मानसिक स्पष्टता आती है।

शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार, जिन बच्चों की नींव मातृभाषा में मजबूत होती है, मातृभाषाओं से इतर भाषाओं में भी उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। मातृभाषाएं परिवार और समुदाय से एक मजबूत भावनात्मक संबंधों की गारंटी भी होती हैं। दुनिया की हर मातृभाषा अपनी संस्कृति, परंपरा और इतिहास की संवाहक है। इसी वजह से दुनियाभर के मानवशास्त्री मानते हैं कि सांस्कृतिक संरक्षण के लिए भाषायी विविधता का संरक्षण जरूरी है। इतना ही नहीं, मातृभाषाएँ आपसी समझ, सम्मान और सहयोग को भी बढ़ावा देती हैं, इस लिहाज से वे समावेशी समाज के निर्माण में भी सहायक मानी जाती हैं। मानवशास्त्रियों के अनुसार, स्थानीय भाषाएँ ज्ञान का खजाना हैं, जिन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाना आवश्यक है। यूनेस्को का मानना है कि सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भाषायी विविधता और बहुभाषावाद का उपयोग सहयोगी हो सकता है। इससे विश्व स्तर पर समावेशी विकास को बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए जरूरी है कि मातृभाषाओं को तकनीक के लिहाज से विकसित किया जाए।

(प्रभासाक्षी डॉट कॉम पर प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

शरद की सुबह

मन में इतनी उलझन
जितने सघन सतपुड़ा वाले वन,
हल्दीघाटी हुई ज़िंदगी
चेरापूँजी हुए नयन ।
जयपुर जैसे लाल गुलाबी
रहे देखते हम सपने,
लेकिन चम्बल के बीहड़ से
रहे गुजरते दिन अपने,
कब से प्यास सँजोये बैठा
बाढ़मेर सा व्याकुल मन।
दिल्ली जैसा दिल बेचारा
जीवन प्रश्नों से जूझे,
उत्तर किन्तु अबूझमाड़ से
रहे अभी तक अनबूझे,
पीड़ायें नित रास रचातीं
समझ हृदय को वृन्दावन।
चाहा बहुत मगर आशायें
शांति निकेतन बनीं नहीं,
चैन हृदय का हुआ गोधरा
जिसने खुशियाँ जनीं नहीं,
इच्छाएँ हरसूद हो गई
उजड़ा जिनका घर आँगन।

- डॉ. राम वल्लभ आचार्य

तेजस का ब्रेक फेल, रनवे से आगे निकला विमान

लैंडिंग के दौरान हादसा, पायलट सुरक्षित, सेना ने सभी 30 विमान ग्राउंड किए

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंडियन एयर फोर्स (आईएएफ) का हल्का लड़ाकू विमान तेजस लैंडिंग के दौरान रनवे से आगे निकल गया। शुरुआती जांच में ब्रेक फेल होने की आशंका जताई जा रही है। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि घटना 7 फरवरी की है। जानकारी अब सामने आई है। विमान ट्रेनिंग उड़ान के बाद एयरबेस पर लौट रहा था। लैंड करते ही पायलट ने ब्रेक लगाने की कोशिश की। जब ब्रेक नहीं लगा तो विमान रनवे से बाहर निकल गया। दुर्घटना से पहले पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया। विमान को नुकसान पहुंचा है।

हादसा किस एयरबेस पर हुआ, ये जानकारी सामने नहीं आई। सूत्रों ने बताया कि इस घटना के बाद, एयरफोर्स ने करीब 30 सिंगल-सीट तेजस जेट के पूरे बेड़े को टेक्निकल जांच के लिए ग्राउंड कर दिया। यानी जांच पूरी होने तक विमान उड़ान नहीं भरेंगे। हादसे पर आईएएफ की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। तेजस जेट से जुड़ा यह तीसरा हादसा है। पहला हादसा मार्च 2024 में हुआ था, जब जैसलमेर के पास एक तेजस जेट क्रैश हो गया था।

दूसरा हादसा नवंबर 2025 में हुआ था जब दुबई एयरशो में एरियल डिस्प्ले के दौरान एक तेजस जेट क्रैश हो गया था। पिछले साल नवंबर में दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया था। हादसा अल मकतूम एयरपोर्ट पर जारी एयर शो में एक डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ। विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई और हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं का गुबार देखा गया।

एयरफोर्स ने बताया कि हादसे में पायलट की भी मौत हो गई। जान गंवाने वाले विंग कमांडर नमांश स्याल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले थे। राजस्थान के पोकरण में भारत शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल तेजस फाइटर जेट मार्च 2024 में क्रैश हो गया था। यह जैसलमेर शहर से 2 किमी दूर जवाहर नगर स्थित भील समाज के हॉस्टल पर जा गिरा। तेजस के क्रैश होने की यह पहली घटना थी।

राहुल गांधी आज भोपाल में, खरगे भी पहुंचेंगे

जवाहर चौक पर ट्रेड डील के खिलाफ होगी किसान महाचौपाल

भोपाल (नप्र)। 24 फरवरी को भोपाल में इंडो-यूएस ट्रेड डील के खिलाफ किसान महाचौपाल होगी। इस महाचौपाल में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। राहुल गांधी दोपहर 1 बजे भोपाल पहुंचेंगे और दोपहर 2 बजे से कार्यक्रम होगा।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भोपाल में राहुल गांधी से पहले पहुंचेंगे। एआईसीसी की ओर से एमपी कांग्रेस को दी गई जानकारी के मुताबिक मल्लिकार्जुन खरगे दोपहर करीब 12 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वे निजी होटल में करीब डेढ़ घंटे रुकेंगे। संगठन प्रभारी संजय कामले मिनट टू मिनट प्रोग्राम अभी नहीं आया है, लेकिन ये तय है कि दोनों नेता करीब पौने दो बजे मंच पर पहुंचेंगे।

जवाहर चौक पर होगी महाचौपाल- कांग्रेस ने राहुल-खरगे की महाचौपाल के लिए लाल परेड ग्राउंड, जवाहर चौक की परमिशन मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने जवाहर चौक पर सभा की अनुमति दी है। जवाहर चौक पर दो बड़े डोम बनाए गए हैं।

50 हजार लोगों के शामिल होने का दावा- पूर्व विधायक संजय यादव ने बताया कि जवाहर चौक पर बनाए गए मंच पर करीब ढाई सौ लोग बैठेंगे। मंच के सामने बड़ा डोम बनाया गया है। करीब 50 हजार लोग इस महाचौपाल में शामिल होंगे।

हाई-वे परियोजना की मंजूरी पर किसान प्रतिनिधि मंडल ने किया मुख्यमंत्री का सम्मान

किसानों की बेहतरी के लिये कर रहे तेज गति से कार्यः सीएम

- **उज्जैन से जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड परियोजना स्थानीय क्षेत्र के समग्र विकास की बनेगी नई पहचान**
- **उड़द उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए हर किसान को देंगे 600 रूपए प्रति क्विंटल बोनस**

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विकास की बात पर हम सब एक हैं। सबके साझा प्रयासों से हम मध्यप्रदेश को देश के विकसित प्रदेशों की श्रेणी में लेकर आएंगे। प्रदेश में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारियों के कल्याण के लिए मिशन मोड पर काम जारी है। इसी कड़ी में हमने जीवाईएएन में आई फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन और आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर इसे ज्ञानी बना दिया है। अब विकास की दिशा में यही हमारा मूल मंत्र है। किसानों की बेहतरी के लिए हम तेजी से कार्य कर रहे हैं। किसानों को अपने उत्पाद देश की बड़ी मंडियों तक पहुंचाने के लिए पहली जरूरत कनेक्टिविटी होती है। किसानों की इस जरूरत को पूरा करने के लिये हमने प्रदेश में सड़क मार्गों और राजमार्गों का जाल बिछाने का बीड़ा उठाया है। उज्जैन से जावरा तक बनने वाली ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड परियोजना (हाई-वे) भी इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। करीब 5017 करोड़ रूपए से अधिक लागत से बनने वाला यह ग्रीनफील्ड हाई-वे इस क्षेत्र के समग्र विकास की एक नई पहचान बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आए किसान प्रतिनिधिमंडल को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का उज्जैन जिले के घट्टिया और नागदा विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में आए किसानों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड परियोजना को जमीन स्तर (नॉन एलीवेटेड पैटर्न) पर त्वरित मंजूरी देने के लिए स्वागत एवं अभिनंदन कर आभार माना। इस अवसर पर घट्टिया विधायक डॉ. सतीश मालवीय, नागदा विधायक डॉ. तेज बहादुर सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को विकास पुरूष बताकर जिले की जनता को यह सौगात देने के लिए गजमाला से अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसान प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि कम समय में ही प्रदेश में बड़ा उल्लेखनीय विकास हुआ है। प्रदेश में विकास से नागरिकों की जिंदगी बेहतर हुई है। प्रदेश में चल रही विभिन्न सड़क परियोजनाओं का लाभ सबसे पहले हमारे किसानों, व्यापारियों के साथ भावी पीढ़ियों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि इंदौर मेट्रोपॉलिटिन सिटी एरिया में शामिल हो जाने से उज्जैन-नागदा-खाचरौद-रतलाम सहित पूरे क्षेत्र का समग्र विकास होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में हमने गंभीर नदी पर बने बांध को जोड़ते हुए एक नए सड़क मार्ग को मंजूरी दी है। इससे उज्जैन और रतलाम के बीच तीन अलग-अलग पहुंच मार्गों से दोनों जिलों का सड़क सम्पर्क और भी सुदृढ़ होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार किसान हितैषी निर्णय ले रही है। हमारी सरकार ग्रीष्मकालीन उड़द पर हर किसान को 600 रूपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लेने जा रही है। सरसों की फसल को भी हम भावांतर भुगतान योजना के दायरे में लेकर आ रहे हैं। चना, मसूर, तुअर और अन्य सभी दलहन और तिलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए हम ठोस कदम उठा रहे हैं। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन फिलहाल देश के कुल दूध उत्पादन का केवल 9 प्रतिशत है, इसे बढ़ाकर हम 20 प्रतिशत तक ले जाने के लिए प्रयासरत हैं।

ग्लोबल टूरिज्म 2026, दुनिया को मिलेंगे 4 सबसे भव्य म्यूजियम

- लॉस एंजिलिस में 'स्पेसशिप', अबू धाबी में कांच के पुल पर गैलरी के साथ बेल्जियम में दिखेगा कार फैक्ट्री म्यूजियम

लंदन (एजेंसी)। वर्ष 2026 वैश्विक संस्कृति और पर्यटन के लिए बेहद खास होने वाला है। अमेरिका के लॉस एंजिलिस से लेकर मध्य एशिया तक दुनिया के चार सबसे प्रतीक्षित म्यूजियम खुलने जा रहे हैं। ये प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्र न केवल शहरों की स्काईलाइन बदलेंगे, बल्कि पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इनमें हॉलीवुड निर्देशक जॉर्ज लुकास का 9 हजार करोड़ रु. का नैरेटिव आर्ट म्यूजियम भी शामिल है।

अमेरिका- यूएफओ जैसा म्यूजियम

लॉस एंजिलिस (अमेरिका) के एक्सपोजिशन पार्क में बन रहा यह म्यूजियम सितंबर तक खुलेगा। 11 एकड़ में फैले परिसर की लागत लगभग 9 हजार करोड़ रु. है। इसका आकार उड़न तश्तरी (यूएफओ-स्पेसशिप) जैसा है। इसमें हॉलीवुड फिल्म 'स्टार वॉर्स' के असली प्रॉप्स सहित 40 हजार कलाकृतियां होंगी।

अबू धाबी-कांच के पुलों पर गैलरियां

धातु की चादरों से बना है यह गुगेनहाइम अबू धाबी म्यूजियम यूएई के सादियात द्वीप पर बन रहा है। यहां कांच के पुलों पर गैलरियां बनाई गई हैं। इसकी लागत लगभग 9 हजार करोड़ रु. है। इसे आर्किटेक्ट फ्रैंक गेहरी ने धातु की चादरों और पाल जैसा डिजाइन किया। यहां जैक्सन पोलक जैसे कलाकारों की कलाकृतियां दिखाई जाएंगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट शिकागो के साउथ साइड में बन रहा है, जो जून 2026 में खुलेगा। 6350 करोड़ रु. की लागत है। इसकी बड़ी खासियत वाइट हाउस के 'ओवल ऑफिस' (राष्ट्रपति का मुख्य दफ्तर) की हूबहू प्रतिकृति होगी। ये 8 मंजिला इमारत ग्रेनाइट पत्थर से बनी है।

बेल्जियम-कार फैक्ट्री म्यूजियम बनी- बेल्जियम के ब्रसल्स में बन रहा यह कनाल-पॉम्पिडू म्यूजियम नवंबर तक खुलेगा। इसे 40 हजार वर्ग मीटर में फैली 1930 के दशक की कार फैक्ट्री को आधुनिक रूप देकर बनाया गया है। यहां पाब्लो पिकासो और हेनरी माटिस जैसे महान चित्रकारों की 350 से ज्यादा कलाकृतियां रखी जाएंगी। यह पुराने औद्योगिक भवनों को नया रूप देगा।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c

न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ मंगलवार, 24 फरवरी 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

सिक्किम में सेना का ऑपरेशन हिमराहत जारी

- बर्फबारी में फंसे 46 टूरिस्टों को सफलता से बचाया

गंगटोक (एजेंसी)। भारतीय सेना ने अचानक हुई बर्फबारी के कारण सिक्किम के शेरेथांग बेल्ट के आसपास फंसे 46 पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया है। सेना के मुताबिक,ऑपरेशन हिमराहत के तहत रेस्क्यू किए पर्यटकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। टूरिस्ट को मौसम के हालात ठीक होने और सड़कें साफ होने तक 17 एमएम माइल पर आर्मी ट्रांजिट कैंप में शिफ्ट कर दिया गया। बर्फबारी में करीब 350 गाड़ियों फंस गई थीं। टूरिस्ट को 150 गाड़ियों से रेस्क्यू किया गया। अभी तक 46 पर्यटकों को ट्रांजिट कैंप में रखा गया है। बचाव-राहत का काम अभी भी जारी है। एएनआई के मुताबिक रविवार सुबह चांगू नाथूला में बर्फबारी के बाद शेरेथांग बेल्ट के जेएन रोड पर सिप्सू और 16एमएम माइल के बीच त्सांगू के पास करीब 350 टूरिस्ट गाड़ियां फंस गईं। ये सभी टूरिस्ट त्सांगू जा रहे थे, जो सिक्किम का पॉपुलर डेस्टीनेशन है। भारतीय सेना सावधानी बरतते हुए इस इलाके में वाहनों की आवाजाही रोक दी। इसके बाद ऑपरेशन हिमराहत शुरू किया। रास्ते में फंसे पर्यटकों और ड्राइवरों को सुरक्षित निकालने के लिए पुलिस,आर्मी और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर किया।

OpHimrahat

कोटद्वार के 'मोहम्मद दीपक' से मिले राहुल गांधी

- नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान का प्रतीक बताया

कोटद्वार (एजेंसी)। कोटद्वार के पटेल मार्ग में दुकान का नाम बदलने को लेकर हुए विवाद के बाद चर्चाओं में आए 'मोहम्मद' दीपक कुमार से सोमवार को दिल्ली में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भेंट की। इस दौरान राहुल गांधी ने पुन: दीपक कुमार को इंसानियत की मिसाल बताया। बताते चलें कि बीती 26 जनवरी को पटेल मार्ग स्थित एक दुकान का नाम बदलने को लेकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान कोटद्वार में जिम संचालक दीपक कुमार ने स्वयं को मोहम्मद दीपक बताते हुए दूसरे पक्ष से शांति बनाए रखने की अपील की। इस दौरान दोनों पक्षों में हाथापाई भी हुई। स्वयं को मोहम्मद दीपक बताने वाला वीडियो 28 जनवरी से सोशल मीडिया पर वायरल होने शुरू हो गया। घटना के चार दिन बाद 31 जनवरी को देहरादून सहित अन्य स्थानों से पहुंचे हिंदू संगठनों ने 26 जनवरी के दिन हिंदू संगठनों पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी को लेकर कोटद्वार में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बाद दुकान स्वामी पटेल मार्ग निवासी वकील अहमद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह पिछले 30 साल से 'बाबा स्कूल ड्रेस' नाम से दुकान चला रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर में सेना का 326 दिनों का ऑपरेशन सफल

व्हाइट नाइट कोर ने किया सैफुल्ला समेत 7 खूंखार आतंकियों का सफाया

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में अपने सफल ऑपरेशन को लेकर विस्तृत जानकारी शेयर की है, जहां आतंकियों के नेटवर्क को सुरक्षाबलों ने एक बड़ा झटका दिया है। यह घटना सुरक्षा बलों द्वारा किश्तवार जिले में एक मुठभेड़ में पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के तीन सदस्यों को मार गिराए जाने के एक दिन बाद हुई है, जिनमें सबसे वांछित आतंकवादी सैफुल्लाह भी शामिल था। दरअसल, एक्स पर एक पोस्ट में, सेना के व्हाइट नाइट कोर ने कहा कि उसने किश्तवार क्षेत्र में 326 दिनों तक अथक और ऊंचाई वाले संयुक्त अभियान चलाए। इसमें कहा गया है कि सुरक्षा बलों ने कड़ाके की ठंड जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दुर्गम इलाकों में आतंकवादियों का पीछा किया, जिसके परिणामस्वरूप कई मुठभेड़ें हुईं। व्हाइट नाइट कोर ने कहा है कि इसमें नागरिक और सैन्य खुफिया एजेंसियों द्वारा स्थापित एक सुव्यवस्थित खुफिया नेटवर्क के आधार पर वाइट नाइट कॉर्प्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सीआरपीएफ के जवानों ने अंततः जीत दर्ज की।

- **खुफिया एजेंसियों के दृढ़ संकल्प,साहस और शौर्य से मिली सफलता**- सेना ने कहा, अभियानों में सहायता के लिए एफपीवी ड्रोन, उपग्रह इमेजरी, आरपीए/यूएवी, संचार आदि जैसी तकनीक का लगातार उपयोग किया गया। सैफुल्लाह और उसके साथियों के खात्मे में परिणत हुई हमारी सेनाओं की अथक खोज और दृढ़ संकल्प यह साबित करता है कि वर्दीधारी हमारे जवानों और खुफिया एजेंसियों के दृढ़ संकल्प, साहस और शौर्य के आगे कुछ भी नहीं टिक सकता। व्हाइट नाइट कोर ने कहा है कि इसमें नागरिक और सैन्य खुफिया एजेंसियों द्वारा स्थापित एक सुव्यवस्थित खुफिया नेटवर्क के आधार पर वाइट नाइट कॉर्प्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सीआरपीएफ के जवानों ने अंतत: चतरू, किश्तवार में सभी सात खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा एजेंसियों को इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी।
- **जंगलों और रिहायशी इलाके के आसपास भी रखी नजर**- सेना को किश्तवाड़ के जंगलों और रिहायशी इलाके के आसपास छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद इनकी घेराबंदी की गई। इनमें सैफुल्लाह भी शामिल था, जो कि एक मोस्ट वांटेड आतंकी था। इसकी तलाश सुरक्षाकर्मियों को काफी समय से थी। सेना ने इनकी घेराबंदी करने और इन्हें भागने से रोकने के लिए सभी एंट्री और एग्जिट पाइंट्स को पूरी तरह से सील कर दिया था। ऐसे में लंबे एनकाउंटर के बाद इन सभी आतंकियों को मार गिराया गया है। रमजान के महीने की शुरुआत से एक दिन पहले यानी 18 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा ने एक आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक, सरकार, वक्फ बोर्ड या किश्तवाड़ की जामिया मस्जिद के इमाम की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन या धार्मिक एवं धर्मार्थ संगठन रमजान के महीने के दौरान चंदा इकट्ठा नहीं कर सकता।

पश्चिम बंगाल की जनता के लिए....

पीएम ने लिखी चिट्ठी

सीएए का जिक्र करते हुए की बांग्लादेशी घुसपैठ पर लगाम की बात

राज्य के विकास के साथ कानून-व्यवस्था पर भी रखे अपने विचार

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नागरिकों के नाम हिंदी और बांग्ला भाषा में एक खुला पत्र लिखा है। इमसें उन्होंने सीएए का जिक्र करते हुए घुसपैठ पर लगाम, राज्य के विकास, कानून-व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दों पर अपनी बात रखी है।

पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री ने पत्र की शुरुआत जय मां काली के जयकारे के साथ की। उन्होंने लिखा कि अब बस कुछ ही महीने में पश्चिम बंगाल का भाग्य सुनिश्चित हो जायेगा। आने वाली पीढ़ी का भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा, यह आपके सोचे-समझे फैसले पर निर्भर करता है। मेरे सोनार बंगाल के सपने देखने वाला हर एक जवान, बूढ़ा और महिलाएं आज बहुत पीड़ा में हैं। उनकी पीड़ा से आज मेरा ह्रदय भी व्यथित है।

- **वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाया** -'अटल पेंशन योजना' के तहत 56 लाख वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाने का सौभाग्य मुझे मिला है। 'उज्ज्वला योजना' के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक परिवारों को रसोई गैस देकर माताओं-बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाकर मैं धन्य हूं। जो किसान पूरे देश का पेट भरते हैं, आज पश्चिम बंगाल में वही अन्नदाता अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे कठिन परिस्थिति में 'किसान सम्मान निधि' के जरिए 52 लाख से अधिक किसानों को सीधे आर्थिक सहायता देकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाई है।

नेपाल में बस हाईवे से नदी में गिरी,18 की मौत

25 घायल, मरने वालों में 2 विदेशी नागरिक,कंट्रोल खोने से हादसा

काठमांडू (एजेंसी)। नेपाल के धादिंग जिले में सोमवार देर रात एक बस हाईवे से नदी में गिर गई। नेपाली मीडिया के मुताबिक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 घायल हैं। मृतकों में एक पुरुष और एक महिला विदेशी नागरिक शामिल हैं। हालांकि, यह किस देश से थे और इनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं। आर्म्ड पुलिस फोर्स के मुताबिक, अब तक 17 शव बरामद किए जा चुके हैं। बाद में एक अन्य यात्री की मौत की पुष्टि हुई, जिससे मृतकों का आंकड़ा 18 हो गया। हादसे में घायल लोगों को रेस्क्यू कर अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अब तक मृतकों और घायलों की पहचान नहीं हो सकी है। बस पोखरा से काठमांडू की ओर जा रही थी, तभी किसी कारण ड्राइवर का बस से नियंत्रण खो गया और बस त्रिशूली नदी में जा गिरी।

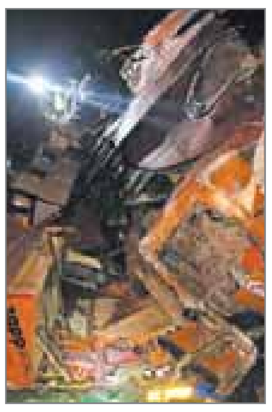

स्नूकर क्लब में छात्र को चाकूओं से गोदा

- कोचिंग के दो साथियों ने तमाचे का बदला लिया; 30 सेकंड में 27 वार किए

भोपाल (नप्र)। भोपाल में 10वीं कक्षा के एक छात्र पर दो नाबालिग छात्रों ने पूल गेम खेलते समय चाकू और छुरी से जानलेवा हमला कर दिया। घटना 15 फरवरी की रात टीला जमालपुरा स्थित गणेश चौक के एक स्नूकर क्लब में हुई।

आरोपियों ने 30 सेकंड में 27 बार चाकू और छुरी मारी। वारदात का सीसीटीवी फुटेज 22 फरवरी को सामने आया है, जिसमें आरोपी फिल्मी अंदाज में अंदर घुसते और ताबड़तोड़ हमला करते दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए।

घायल छात्र किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा। हमले में उसकी एक कलाई पर 10 से अधिक गहरे कट लगे हैं, जबकि दूसरे हाथ की दो उंगलियां कट गई हैं। कंधे और पीठ पर भी गंभीर चोटों के निशान हैं। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है।

पुलिस के अनुसार, घायल 16 वर्षीय छात्र गौतम नगर थाना क्षेत्र का निवासी है और रोजाना पूल खेलने क्लब आता था। कुछ दिन पहले उसका क्लब में ही 16-16 वर्षीय दो अन्य नाबालिगों से विवाद हो गया था। बताया जा रहा है कि उस दौरान छात्र ने दोनों को थप्पड़ मार दिए थे। इसी रंजिश में आरोपियों ने बदला लेने की नीयत से हमला किया।

हमला करने वाले दोनों नाबालिग भी 10वीं कक्षा के छात्र हैं और घायल के साथ कोचिंग में पढ़ते हैं। पूल गेम में वर्चस्व को लेकर दोनों पक्षों में पहले भी तनातनी हो चुकी थी। पुलिस कार्रवाई पर सवाल, आरोपियों को नोटिस देकर थाने से छोड़ा

पुलिस ने साधारण धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद नोटिस देकर थाने से छोड़ भी दिया गया। मामले में सब इंस्पेक्टर मनिपाल सिंह भदौरिया ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। दोनों ही नाबालिग बालकों को थाने से नोटिस देकर छोड़ दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर आगे धाराओं में इजाफा होगा।

एमपी के कूनो में चीतों की 'हाफ सेंचुरी' की तैयारी

समंदर पार से उड़कर आ रही है 8 चीतों की नई खेप

श्योपुर (नप्र)। मध्य प्रदेश में चीतों को फिर से बसाने और उनकी सुरक्षा के प्रयासों को बड़ा बढ़ावा मिला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि 28 फरवरी तक बोत्सवाना से 8 और चीते मध्य प्रदेश आ जाएंगे। यह कदम इस साल के अंत तक राज्य में चीतों की संख्या 50 तक पहुंचाने के मुख्यमंत्री के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। इसी बीच, दक्षिण अफ्रीका की मादा चीता गामिनी ने 18 फरवरी को कूनो नेशनल पार्क में तीन शावकों को जन्म दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा में चीता पुनर्प्रजनन परियोजना की सराहना करते हुए कहा कि इसने 'प्रकृति से प्रगति' का एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि 'प्रोजेक्ट चीता' दुनिया का सबसे सफल वन्यजीव संरक्षण अभियान बनकर उभरा है। शनिवार को सरकार ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर 'प्रोजेक्ट चीता' के 'तीन सफल वर्षों' पर प्रकाश डाला। विज्ञप्ति में कहा गया, भारत की चीता विलुप्ति के बाद उन्हें फिर से देश में बसाने की पहल ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। विज्ञप्ति में आगे कहा गया, सितंबर 2022 में शुरू हुई यह संरक्षण यात्रा लगातार जारी है।

- **चीतों को जम गई कूनो की आबोहवा**- नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीते भारतीय परिस्थितियों में अच्छी तरह से ढल गए हैं। कूनो और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में दूसरी पीढ़ी के शावकों का जन्म सीएम मोहन यादव के प्रभावी नेतृत्व में पीएम मोदी के दृष्टिकोण की प्राप्ति को दर्शाता है। भारतीय अभयारण्यों में चीतों को दौड़ते देखना जैव विविधता संरक्षण के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया है। इससे पहले, 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने नामीबिया से लाए गए आठ चीतों को कूनो नेशनल पार्क के संरक्षित बाड़ों में छोड़ा था, जिसने महत्वाकांक्षी चीता पुनर्प्रजनन परियोजना की औपचारिक शुरुआत की थी। 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को कूनो में लाया गया था। सरकार का लक्ष्य 2032 तक लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 60-70 चीतों की एक आत्मनिर्भर आबादी स्थापित करना है।
- **प्रोजेक्ट चीता पर सरकार की प्लानिंग**- 28 फरवरी तक बोत्सवाना से 8 नए चीते एमपी की धरती पर कदम रखेंगे, जिससे कूनो की रौनक और बढ़ेगी। सीएम मोहन यादव ने विधानसभा में 'मिशन 50' का ऐलान किया है, यानी इसी साल के भीतर चीतों की संख्या 50 पार कराने की तैयारी है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी मादा चीता गामिनी ने 18 फरवरी को 3 शावकों को जन्म दिया है, जिससे प्रोजेक्ट को बड़ी मजबूती मिली है। सीएम ने इस अभियान को 'प्रकृति से प्रगति' का संदेश बताया है और इसके लिए पीएम मोदी के विजन का आभार जताया है। सरकार केवल कूनो ही नहीं, बल्कि गांधी सागर और गुजरात के बन्नी घास के मैदानों में भी चीतों का घर बसाने की लंबी योजना पर काम कर रही है।

कनाडा के 3 पंजाबी सांसदों की सीक्रेट विजिट पर विवाद

- पूछा जा रहा-यात्रा पर खर्चा किसने किया

लुधियाना (एजेंसी)। कनाडा में मुख्य विपक्षी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा के पंजाबी मूल के 3 सांसदों की पंजाब यात्रा पर सवाल उठ रहे हैं।

कनाडा में सोशल मीडिया पर तीनों कंजर्वेटिव सांसदों से पूछा जा रहा है कि उनकी इस यात्रा का खर्च किसने उठाया।

कनाडा के सांसद जसराज सिंह हल्लां, अमरप्रीत सिंह गिल और दलविंदर सिंह गिल पंजाब यात्रा पर आए थे। यात्रा का कारण और इस यात्रा के बारे में जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई, इस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। यही नहीं, सांसदों के आसपास हथियारबंद निहंगों के होने पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यात्रा से जुड़ी बातें और अन्य गतिविधियों से जुड़े फोटो-वीडियो लोगों ने सोशल मीडिया पर अपलोड किए। इसके बाद सांसदों की यात्रा का खुलासा हुआ।

- **गोल्डन टेंपल, गुरु की रसोई व परगट सिंह से मिले**- तीनों सांसद 15 फरवरी को अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब (गोल्डन टेंपल) गए और वहां माथा टेका। उसके बार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने उन्हें सम्मानित किया। सदस्यों व अन्य धार्मिक नेताओं के साथ बैठक की। उसके बाद वह कांग्रेस विधायक परगट सिंह से मिले और उनके साथ इमीग्रेशन के मुद्दे पर बातचीत की। बाद में वे होशियारपुर में गुरु की रसोई में गए।

- योगी ने सिंगापुर में किए 6 हजार करोड़ के समझौते

यूपी में 20 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

लखनऊ (एजेंसी)। सीएम योगी सिंगापुर दौरे पर हैं। उन्होंने कारोबारियों के साथ बैठक की। यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया। यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ 6,650 करोड़ रुपए के निवेश के लिए तीन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह निवेश ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और हाइपरस्केल डेटा सेंटर जैसे अहम क्षेत्रों में किया जाएगा। इनसे 20 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने निवेशकों को बताया- हम निवेशकों को आसान और तेज मंजूरी दे रहे हैं। यूपी की 25 करोड़ से ज्यादा की बड़ी आबादी एक बड़ा बाजार है। कानून-व्यवस्था बेहतर है, एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी मजबूत हो रही, जिससे लंबे समय के निवेशकों को फायदा मिलेगा। सीएम के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और उद्योग मंत्री नंद गोपाल नंदी नजर आए। नंदी और वित्त मंत्री कोट-पैंट पहने हुए थे, जबकि सीएम पारंपरिक परिधान यानी भगवा कपड़ों में नजर आए। सीएम 3 दिन में 25 कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 25 फरवरी को जापान पहुंचेंगे।

रिश्तों में आई नई गर्माहट, व्यापार और तकनीक में भी बढ़ेंगे साथ

- भारत की मेजबानी देख भावुक हुए ब्राजील के राष्ट्रपति लूला

भारत-ब्राजील व्यापार लक्ष्य 30 अरब डॉलर तक बढ़ाया गया

नई दिल्ली (एजेंसी)। ब्राजील के राष्टपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने भारत यात्रा के दौरान मिले सांस्कृतिक सम्मान और आत्मीय आतिथ्य की खुलकर सराहना की। इंडिया-ब्राजील इकोनामिक फोरम में उन्होंने कहा कि राजकीय भोज और दोपहर के भोजन के दौरान भारतीय संगीतकारों द्वारा ब्राजीलियाई गीतों की प्रस्तुति से वह अचंभित और भावुक हो गए। राष्ट्रपति लूला ने याद किया कि पिछले वर्ष जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ब्राजील गए थे, तब उन्होंने साओ पाउलो से गायक बुलाकर प्रधानमंत्री के पसंदीदा गीत की प्रस्तुति पैलेसियो डा अल्वोराडा में कराई थी। उन्होंने कहा कि भारत बहुत बड़ा दिल रखता है।

- **दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने का लक्ष्य**- दोनों देशों के बीच व्यापार 2.4 अरब डॉलर से बढ़कर 10.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। जहां 2030 तक 20 अरब डॉलर व्यापार का लक्ष्य रखा गया था, वहीं लूला ने इसे बढ़ाकर 30 अरब डॉलर तक ले जाने की महत्वाकांक्षा जताई। यात्रा के दौरान भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और ब्राजील की स्वास्थ्य नियामक एजेंसी के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान हुआ।

परिक्रमा

एआई स्टेट मिशन लांच करेगा मध्यप्रदेश

अरुण पटेल

लेखक सुबह सवेरे के प्रबंध संपादक हैं

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एआई समिट 2026 में भाग लेते हुए देश की राजधानी दिल्ली में मध्यप्रदेश पेवेलियन का भ्रमण करते हुए स्टार्टअप से लेकर अन्य सेक्टर के प्रदर्शन को देखा और दावा किया कि नवाचार में चुनौती तो होती है लेकिन डरने की बजाय इससे पार होने पर काम करना चाहिए। मध्यप्रदेश जल्द ही एआई स्टेट मिशन लांच करेगा और एआई का सुशासन और विकास के लिए इस्तेमाल करेगा। उनका यह भी मानना है कि धार्मिक पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र में एआई का उपयोग कैसे हो सकता है इस भी विचार करेंगे। सिंहस्थ 2028 उज्जैन में 40 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं, इस महाकुंभ में भीड़ नियंत्रण से लेकर लोगों को सुदृढ़ बनाने में भी एआई की मदद लेंगे।

डॉ. यादव का यह भी मानना है कि शिक्षा, बिजली और पर्यटन में एआई के बेहतर उपयोग को लेकर हमारा सर्वाधिक फोकस रहेगा। खासतौर पर कृषि में ज्यादा उत्पादन, फसल की बीमारियों का पता लगाने सहित अन्य बीमारियों पर एआई का उपयोग होगा। हर एक किसान इसका कैसे उपयोग करेगा यह जरुर चुनौती है, लेकिन कृषि विभाग एआई का कैसा उपयोग करे इस पर विचार हो रहा है। जहां तक डॉ. यादव के दावे का सवाल है उसमें दो-मत नहीं हो सकते कि यदि सरकार चाहेगी तो वह कर सकती है, लेकिन इसके पूर्व उसको किसानों और विभाग में तालमेल बिठाने पर कड़ाई बरतना होगी। कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानोन्मुख बनाना होगा ताकि वे सरल भाषा में किसानों को यह समझा सकें कि हम आपके हित में यह कर रहे हैं और किसान भी उसमें सहमत होकर अपनी पूरी सहभागिता करें। मध्यप्रदेश जो कि देश का दिल है की खूबियों का बखान करते हुए डॉ. यादव यह भी फरमाते हैं कि यहां पर ट्रांसपोर्टेशन आसान है इसलिए एआई हब बनने की संभावना है और सरकार एआई के निवेश के लिए हरसंभव सहयोग करेगी। प्रदेश में डाटा सेंटर बनाने की भी काफी संभावना है। जहां तक लाजिस्टिक हब का सवाल है उसमें भी बेहतर डेस्टीनेशन है इसलिए उन्होंने निवेशकों से प्रदेश में आकर निवेश करने का आह्वान किया है।

मध्यप्रदेश में इन दिनों विधानसभा सत्र चल रहा है इसलिए आरोप-प्रत्यारोपों की भी झड़ी लगी हुई है क्योंकि यह ऐसा अवसर होता है जिसमें हर विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाता है। जहां तक मध्यप्रदेश के भारी-भरकम घाटे का सवाल है उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा यह दावा कर रहे हैं कि सरकार ऋण इसलिए ले रही है कि वह राज्य के वित्तीय संसाधनों का एक स्त्रोत है। इसके साथ ही उन्होंने यह आरोप भी मढ़ा कि कांग्रेस सरकार ने ऋण लेकर उस राशि का वेतन और भत्तों में व्यय किया, लेकिन वित्तीय वर्ष 2019-20 में जबकि मध्यप्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो ऋण लिया गया उससे राजस्व घाटे की स्थिति बनी। लेकिन हमारी सरकार ने जो ऋण लिया है उससे सड़कें, स्कूल, अस्पताल, पेयजल व सिंचाई की परियोजनाओं आदि में खर्च किया जा रहा है और उससे अधोसंरचना निर्मित की हैं जो कि आगे कई वर्षों तक प्रदेश की धरोहर रहेंगी और विकास में भी सहायक बनेंगी। जहां तक विकास में सहायक बनने का सवाल है उस स्थिति को पूरी तरह से जमीनी धरातल पर उतारने के लिए नौकरशाही पर भी सरकार को कड़ी नजर रखना होगी क्योंकि कभी-कभी वह अच्छी से अच्छी योजना को भी विफल कर देती है। हालांकि पिछले कुछ समय से देखा गया है कि सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है। यदि एक बार अधोसंरचना विकसित हो गयी तो फिर प्रदेश की प्रगति में जो पंख लगेंगे उन्हें कोई चाह कर भी नहीं रोक पायेगा। कोविडकाल की त्रासदी का उल्लेख करते हुए उपमुख्यमंत्री यह भी कहते हैं कि 2019-20 से लेकर 20-21 के कार्यकाल को छोड़ दें तो सरकार निरंतर राजस्व आधिक्य में रही है।

इंफ्रा के लिए ढाई सौ अरब डालर का निवेश- इन दिनों विश्व फलक पर आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस यानी एआई की बाढ़ आई हुई है। इसमें तेजी से निवेश भी बढ़ रहा है। हालांकि 2025 में इस क्षेत्र में कुल निवेश में भारत की हिस्सेदारी भी रही है। भारत को इंफ्रा स्ट्रक्चर और डेटा सेंटर डेवलपमेंट के लिए ढाई सौ अरब डालर के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिनमें इनवेस्टमेंट का वायदा किया गया है उनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए 110, अदानी समूह के लिए 100, माइक्रो साफ्ट के लिए 50, अमेजन के लिए 35, गूगल के लिए 15.5 और योट्टा के लिए 2 अरब डालर के निवेश का भरोसा दिलाया गया है। इसकी घोषणा अमेजन ने पिछले साल की थी। भारत भले ही बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर या मेमोरी चिप का निर्माण नहीं करता है लेकिन इलेक्ट्रिकल इक्यूपमेंट और इंजीनियरिंग सप्लाई चेन में उसकी प्रभावी मौजूदगी है। विशेषज्ञ एआई बूम से लेकर पॉवर इक्यूपमेंट, जनरेटर और एवीएसी यानी हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में मौके दिखते हैं। यानी सिर्फ टेक्नालाजी में नहीं, पूरे इंडस्ट्रीयल इनवेस्टमेंट साइकल में तेजी आ सकती है।

बंदियों की सोच सकारात्मक बनाने के प्रयास हों : राज्यपाल श्री पटेल

बंदी पुनर्वास प्रयासों को समग्रता और बहुआयामी स्वरूप दें

लोकभवन
मध्य प्रदेश

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि बंदी पुनर्वास प्रयासों को समग्रता और बहुआयामी स्वरूप में किया जाना चाहिए। कार्य का दृष्टिकोण मानवतावादी हो। भाव संवेदनशील और विचारशील होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास प्रयासों में सकारात्मक सोच के निर्माण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का 'मन की बात' कार्यक्रम बंदियों की सोच को रचनात्मक दिशा देने। भविष्य के प्रति विश्वास और आत्मबल को मजबूत करने में बहुत सहयोगी होगा।

राज्यपाल श्री पटेल सोमवार को लोकभवन में गृह एवं जेल विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह श्री शिव शेखर शुक्ला, राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, विशेष महानिदेशक जेल श्री अखितो सेमा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल श्री पटेल ने अधिकारियों से कहा कि बंदी उत्पादक गतिविधियों के द्वारा बंदियों के परिवारों के जीवन निर्वाह में आर्थिक सहयोग के उद्देश्य से नियोजन गतिविधियों का संयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि जेलों में बंद मामूली अपराधों के विचाराधीन कैदियों को केवल दंड देना ही नहीं, बल्कि उन्हें सकारात्मक सुधार के जरिए समाज की मुख्य धारा में वापस भेजना पुनर्वास प्रयासों का मूलाधार होना चाहिए। भाव उनको अपराधी की पहचान से मुक्त होकर बेहतर नागरिक के रूप में स्थापित होने में मदद का होना चाहिए। समाज के नव-निर्माण में वे अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकें।

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि 'मन की बात' कार्यक्रम को सुनकर जेल की दीवारों के पीछे एकाकी जीवन जी रहे बंदियों को देश की प्रगति और प्रेरक कहानियों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। उनके जीवन में आशावाद और नव-निर्माण का संचार होगा। बंदियों के भीतर छिपी नकारात्मकता में कमी आएगी। सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्म-सुधार की भावना जागृत होगी। उन्होंने जेलों में लंबित दया याचिकाओं, महिला बंदियों के बच्चों के उचित लालन-पालन की व्यवस्थाओं, महिला बंदियों के पुनर्वास, दिव्यांग एवं बुजुर्ग बंदियों के लिए आवश्यक कृत्रिम उपकरणों की उपलब्धता और श्रम शक्ति के उत्पादक गतिविधियों में नियोजन के संबंध चर्चा की। अपर मुख्य सचिव गृह श्री शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि वर्ष 2025-26 में प्राप्त 18 दया याचिकाओं का प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर परीक्षण किया जा रहा है। जेल विभाग द्वारा विगत पांच वर्षों में प्राप्त सभी दया याचिकाओं का परीक्षण कराया जा रहा है। विभाग द्वारा उनके त्वरित निराकरण के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 180 देशों के 11 लाख लोगों के द्वारा देखे जाने वाले गीता पाठ के ऑनलाइन कार्यक्रम का प्रदेश की जेलों में प्रसारण की अभिनव पहल जेल विभाग द्वारा की गई है। साप्ताहिक प्रसारण में गीता के श्लोक का शुद्ध उच्चारण और श्लोक का भावार्थ कर समझाया जाता है।

चलती गाड़ी में ड्राइवर की बिगड़ी तबीयत, खंबे से टकराई , घायल

भोपाल (नप्र)। भोपाल के शाहपुरा लेक के पास इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के सामने सोमवार को एक हादसा हो गया। यहां एक कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे स्ट्रीट लाइट के खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन के अगले हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा। कार की नंबर प्लेट पर 'मध्य प्रदेश प्रशासन' लिखा हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ड्राइवर पास के पेट्रोल पंप से तेल भरवाकर लौट रहा था। इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। जिससे वह वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और कार बिजली के खंभे से जा टकराई। हादसे के वक्त कार में केवल ड्राइवर ही मौजूद था। बताया जा रहा है कि ड्राइवर के सीने में तेज दर्द हुआ था। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे और घायल ड्राइवर को एक निजी अस्पताल पहुंचाया। उसकी हालत को लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

किसानों को लाभान्वित करने हम खेत से बाज़ार तक तैयार कर रहे पूरी श्रृंखला : मुख्यमंत्री

कृषि में शोध बढ़ायेंगे, मंडी निर्यात नीति भी लायेंगे

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसान हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ हैं। इनके अथक परिश्रम से ही हमारे बाजार गुलजार है। हम वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। यह वर्ष प्रदेश के इतिहास में किसानों के हित और समग्र कल्याण के मामले में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह वर्ष 'खेत से लेकर कारखाने तक और बाग से लेकर बाजार तक' की पूरी मूल्य संवर्धन श्रृंखला को एक सूत्र में जोड़ेगा। इस वर्ष हम कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और इनमें वैल्यू एडिशन के लिए अधिकाधिक रोजगार आधारित उद्योगों के विकास, उन्नत किस्म के बीजोत्पादन, पशुपालन, दुग्धोत्पादन, मत्स्योत्पादन में वृद्धि सहित हर वो कदम उठाएंगे, जिनसे खेती और अन्नदाताओं का विकास हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास से कृषि विश्वविद्यालय परिसर, ग्वालियर में हो रहे 'कृषि मंथन एवं कृषि प्रौद्योगिकी मेला 2026' को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में राष्ट्रय नदी जोड़ो परियोजना संबंधी कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में तेज़ी से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। हमारी सरकार प्रदेश में औषधीय और मसाला फसलों का उत्पादन बढ़ाने के सभी प्रयास कर रही है। हम जल्द ही कृषि उत्पादन निर्यात नीति लाने वाले हैं। हम कृषि में शोध कार्य भी बढ़ायेंगे। उन्होंने कहा कि हम खेती-किसानी और फल-फूलों की खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए कोई कसर नहीं रखेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस कृषि मंथन से जो अमृत निकलेगा, वह हमें किसानों के कल्याण के लिये प्रभावी और कारगर कदम उठाने में सहायक होगा। 'कृषि मंथन' राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) नई दिल्ली और कृषि विभाग, म.प्र. शासन के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है।

सरसों पर भी भावांतर

उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरसोंकी जनवरी महीने में औसत मंडी दरें 6000 रुपए प्रति क्विंटल हैं। सरसों का केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 6200 रुपए प्रति क्विंटल हैं। हमारी सरकार ने सरसों का उपार्जन भावांतर योजना के नियत प्रावधानों के तहत कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने का निर्णय लिया है। इसे लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। इस योजना अंतर्गत एफएक्यू सरसों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम राशि मिलने की प्रतिपूर्ति के लिए योजना प्रस्तावित की गई है।

सीएम यादव ने पांच फसलों पर की बड़ी घोषणा

सीएम मोहन यादव ने विधानसभा में पांच फसलों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने सदन में कहा कि किसानों का सशक्तिकरण ही हमारे प्रदेश के सर्वांगीण विकास की आधारशीला है। अब एमपी में किसानों को उड़द पर भी बोनस मिलेगा। साथ ही सरसों पर भावांतर देने की घोषण की है। सीएम ने कहा कि साल 2026 कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। मोहन यादव ने कहा कि किसान कल्याण के लिए पांच प्रमुख फसलों पर बड़ी घोषणा की है। इसमें उड़द, सरसों, चना, मसूर और तुअर है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सरसों के रकबे में पूर्व वर्ष की तुलना में लगभग 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और द्वितीय अग्रिम अनुमान अनुसार अनुमानित उत्पादन 15.71 लाख मीट्रिक टन है। कृषि उपजों के लिए सरकार की मूल्य नीति का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है, जिससे प्रदेश में सरसों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके।

मप्र हाईकोर्ट ने लगाई रोक

सरकार रोजगार सहायकों का नहीं कर सकेगी ट्रांसफर-टर्मिनेशन

मार्गदर्शिका 2025 पर 4 सप्ताह में जवाब मांगा, कलेक्टर-कमिश्नर को भी आदेश भेजा

जबलपुर (नप्र)। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार को ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका 2025 पर भी रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सरकार आदेश दिया है कि आगामी आदेश तक किसी भी रोजगार सहायक का ट्रांसफर और टर्मिनेशन नहीं होगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अधिवक्ता गोपेश तिवारी ने बताया कि हाईकोर्ट ने सरकार की मार्गदर्शिका के क्रियान्वयन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह आदेश मनरेगा कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वल्लभ भवन और हर जिले के कलेक्टर को भेजा जा रहा है, ताकि कहीं भी रोजगार सहायक का ट्रांसफर ना हो सके।

मार्गदर्शिका पर टर्मिनेशन-ट्रांसफर नीति के खिलाफ याचिका

अधिवक्ता तिवारी के मुताबिक राज्य सरकार ने एक नई मार्गदर्शिका जारी कर रोजगार सहायकों के टर्मिनेशन और ट्रांसफर नीति निर्धारित की थी। हालांकि, इस नीति का क्रियान्वयन अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है।

इसी बीच रोजगार सहायकों ने हाईकोर्ट में स्थानांतरण नीति और सेवा समाप्ति से संबंधित शर्तों को चुनौती दी थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने याचिका में सुनवाई की और मार्गदर्शिका 2025 पर रोक लगा दी।

रोजगार गारंटी योजना लागू होने के बाद हुई थी रोजगार सहायकों की भर्ती- दरअसल, देश में रोजगार गारंटी योजना लागू होने के बाद ग्रामीण स्तर पर कार्यों की मॉनिटरिंग और मजदूरों का रिकॉर्ड रखने के लिए रोजगार सहायकों की भर्ती की गई। मध्य प्रदेश में उस वक्त शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी। राज्य में लगभग 25 हजार पदों पर भर्ती की गई।

प्रारंभिक चरण में रोजगार सहायकों को प्रतिमाह 9 हजार रुपए मानदेय निर्धारित किया गया था। बाद में सरकार ने यह महसूस किया कि निर्धारित मानदेय कार्य की तुलना में कम है। इसके बाद दो अन्य मदों के माध्यम से अतिरिक्त 9 हजार रुपए जोड़ दिए गए।

रोजगार सहायकों को 18 हजार रुपए मानदेय

इस तरह रोजगार सहायकों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 18 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया गया। अधिकांश रोजगार सहायकों की नियुक्ति उनके पैतृक या निवास ग्राम में ही की गई थी। भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर संबंधी योग्यता को प्राथमिकता दी गई थी। चयन के लिए 12वीं कक्षा के प्राप्तांक और पीजीडीसीए जैसी कंप्यूटर डिग्री को आधार बनाया गया था। वर्तमान में भी अधिकांश रोजगार सहायक उसी ग्राम पंचायत में कार्यरत हैं, जहां उनकी नियुक्ति हुई थी।

ग्रामीण स्तर पर कई ग्राम सचिवों को कंप्यूटर संचालन का अनुभव सीमित होने के कारण पंचायतों में डिजिटल कार्यों और ऑनलाइन प्रविष्टियों की जिम्मेदारी रोजगार सहायक ही निभा रहे हैं।

समाधान योजना के दूसरे चरण में शामिल होने के लिए 5 दिन शेष

अब तक 20 लाख 26 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने लिया सरचार्ज में छूट का लाभ : ऊर्जा मंत्री श्री तोमर

भोपाल (नप्र)। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 का द्वितीय व अंतिम चरण 28 फरवरी तक लागू है। योजना में शामिल होकर लाभ उठाने के लिए अब केवल 5 दिन शेष हैं। इस दौरान तीन माह से अधिक के बकायादार उपभोक्ताओं को एकमुश्त राशि जमा करने पर 90 प्रतिशत तक सरचार्ज में छूट का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल 3 नवंबर से शुरू हुई समाधान योजना 2025-26 में शामिल होकर अभी तक 20 लाख 26 हजार बकायादार उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ लिया है।

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि तीन माह से अधिक के बकायादार जो उपभोक्ता योजना के प्रथम चरण में शामिल नहीं हो पाए वे अब द्वितीय चरण में शामिल होकर अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करके 90 फीसदी तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं।

मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 में अब तक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 5 लाख 98 हजार बकायादार उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराकर लाभ लिया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में 578 करोड़ 97 लाख से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 272 करोड़ 76 लाख रूपए का सरचार्ज माफ किया गया है। इस तरह पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 7 लाख 44 हजार उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया है। कंपनी के खाते में 205 करोड़ 20 लाख रूपये जमा हुए हैं, जबकि 68 करोड़ 6 लाख रूपये का सरचार्ज माफ किया गया है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 6 लाख 84 हजार उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया है। कंपनी के खाते में 186 करोड़ 83 लाख रूपये जमा हुए हैं, जबकि 28 करोड़ 16 लाख रूपये का सरचार्ज माफ किया गया है।

मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के लागू होने से उपभोक्ता बकाया बिल की एकमुश्त राशि जमा कर अधिकतम छूट का लाभ ले रहे हैं। यह योजना उन बकायादार उपभोक्ताओं के लिए वरदान बनी है जो सरचार्ज के कारण मूलधन राशि जमा नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें समाधान योजना के द्वितीय चरण में सरचार्ज में 50 से लेकर 90 प्रतिशत तक छूट के साथ एकमुश्त अथवा किस्तों में भुगतान करने का विकल्प मिल रहा है।

समाधान योजना 2025-26 : एक नजर में

समाधान योजना 2025-26 का उद्देश्य 3 माह से अधिक अवधि के उपभोक्ताओं को बकाया विलंबित भुगतान के सरचार्ज पर छूट प्रदान करना है। यह योजना जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं के सिद्धांत पर आधारित है। इस योजना में द्वितीय और अंतिम चरण 01 फरवरी से शुरू हो चुका है जो कि 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। दूसरे चरण में एक मुश्त भुगतान करने पर 70 से 90 फीसदी तथा किस्तों में भुगतान करने पर 50 से 60 फ़ीसदी तक सरचार्ज माफ किया जा रहा है। समाधान योजना 2025-26 का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को कंपनी के पोर्टल पर पंजीयन करना है। पंजीयन के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं। विस्तृत विवरण तीनों कंपनियों की वेबसाइटों पर भी देखा जा सकता है।

बड़े तालाब से अतिक्रमण-प्रदूषण हटाने सांसद ने बुलाई बैठक

बोले-वक्फ की जागीर हो गया भोपाल, कलेक्टर ने पूछा-कितना अतिक्रमण बचा, बगलें झांकने लगे एसडीएम, कहा-एक हफ्ते में हटाएं

भोपाल (नप्र)। बड़े तालाब को अतिक्रमण और प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से सांसद आलोक शर्मा ने सोमवार को कलेक्टोरेट में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह, एडीएम अंकुर मेश्राम, नगर निगम अपर आयुक्त तन्मय वशिष्ठ शर्मा, सभी एसडीएम सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। यहां सांसद ने बड़े तालाब का मास्टर प्लान नए सिरे से तैयार करने को कहा, तो कलेक्टर पूछ बैठे कि तालाब के आसपास कितना अतिक्रमण बचा है। इस पर सभी एसडीएम बगलें झांकने लगे।

सांसद ने कहा कि बड़ा तालाब आज गंभीर प्रदूषण और अतिक्रमण की चपेट में है। तालाब का कुल भराव क्षेत्रफल 31 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन अतिक्रमण और सूखे के कारण यह क्षेत्र 8-9 किलो मीटर में ही सिमट कर रह गया है। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से पूछा कि तालाब में कितने गंदे नालों का पानी मिल रहा है और कितने नालों का पानी रोकने के लिए एसटीपी बनाए हैं। तालाब के पास फार्म हाउस नहीं बन सकते, फिर भी फार्म हाउस-मकान बन रहे हैं। जिससे तालाब की सीमा खत्म हो रही है।

उन्होंने पूछा कि बड़े तालाब से अतिक्रमण हटाने के लिए एनजीटी ने अब कितने आदेश जारी किए हैं ? कितने आदेशों का पालन जिला प्रशासन और नगर निगम ने किया है। तालाब के आसपास भविष्य में कोई अतिक्रमण न हो और एनजीटी के आदेश पर अमल करने के लिए कोई टीम गठित की है क्या? इस टीम ने क्या-क्या कार्यवाही की है?

एसडीएम को दी हफ्तेभर की मोहलत- कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने सभी एसडीएम से अलग-अलग चर्चा कर जानना चाहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्रवाई की। उन्होंने हफ्तेभर की मोहलत चारों एसडीएम को दी है कि एक हफ्ते में सभी मेजर प्राइमा फेसी अतिक्रमण बड़े तालाब के किनारे से हटाए जाएं। उन्होंने साफ कर दिया कि अब हर हफ्ते अतिक्रमण हटाने और प्रदूषण रोकने के संबंध में समीक्षा बैठक की जाएगी।

वक्फ बोर्ड की जागीर हो गया भोपाल- सांसद शर्मा ने पूछा कि भदभदा डेम के पास प्रेमपुरा से 227 झुग्गियां पहले हटाई गई हैं पर अभी भी 26 झुग्गियां बची हैं, वे अभी तक क्यों नहीं हटाई गईं? उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज पूरा भोपाल वक्फ बोर्ड की जागीर हो गया है। भोपाल की जनता की सहुलियत के लिए मेट्रो ट्रेन की लाइन डालो, तो कहते हैं कि यह वक्फ की जमीन है।

जब मैं भोपाल का महापौर था तब मैंने पोलेटेक्निक चौराहा से डिपो चौराहा तक स्मार्ट रोड बनानी चाही, तब भी कहने लगे यह वक्फ की जगह है। लेकिन तब मैंने स्मार्ट सिटी रोड बनाकर भोपाल की जनता की सेवा की। इसी प्रकार से जब भोपाल के हमीदिया रोड स्थित सब्जी मंडी की जगह पर पीपीपी मॉडल पर बस स्टैंड बनाने गए, तो कहते हैं कि यह वक्फ बोर्ड की जगह है।

संपादकीय

भारत-ब्राजील में अहम समझौता

भारत और ब्राजील के बीच दुर्लभ खनिज रक्षा क्षेत्र में हुए 20 अरब डॉलर के करार के साथ-साथ और भी कई समझौते दोनों देशों के बीच दृढ़ होते रिश्ते और रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के न्यौते पर चार दिनी दौरे पर भारत आए थे। इस दर्मियान ये समझौते हुए। गौरतलब है कि ब्राजील लौह अयस्क, मैंगनीज, निकल और नियोबियम जैसे खनिजों का विश्व के प्रमुख उत्पादकों में है। भारत की इस्पात उत्पादन क्षमता 218 मिलियन टन तक पहुंच चुकी है और आधारभूत ढांचे के विस्तार के साथ इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा की मौजूदगी में भारत और ब्राजील ने क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। साथ ही इस्पात आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण समझौता हुआ। यह आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, सामरिक स्वावलंबन और आर्थिक शक्ति के नए युग की घोषणा है। इसी संदर्भ में ब्राजील के सरकारी बैंक बैंको डो ब्राजील की अध्यक्ष टार्सियाना मेडेरोस ने कहा है कि उनका बैंक भारत-ब्राजील व्यापार को बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने में रणनीतिक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में आयोजित भारत-ब्राजील बिजनेस फोरम में उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसमें अभी और बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि कृषि, ऊर्जा, खनिज, दवा, तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग ऐसे सेक्टर हैं जिनमें सहयोग बढ़ाकर व्यापार को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। समझौते के बाद साझा प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 'मेरे प्यारे दोस्त' बताते हुए कहा कि हम दोनों सिर्फ ग्लोबल साउथ की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं हैं। यह एक डिजिटल सुपरपावर और एक रिन्यूएबल एनर्जी सुपरपावर की मीटिंग है। पीएम मोदी ने कहा कि ब्राजील ने डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोएलिशन की को-चेयर करने का भी प्रस्ताव दिया है। ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। हम अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन डॉलर से आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स पर हुआ समझौता मजबूत और लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उल्लेखनीय है कि ब्राजील लौह अयस्क, मैंगनीज, निकल और नियोबियम जैसे खनिजों का विश्व के प्रमुख उत्पादकों में है। भारत की इस्पात उत्पादन क्षमता 218 मिलियन टन तक पहुंच चुकी है और आधारभूत ढांचे के विस्तार के साथ इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में क्रिटिकल मिनरल्स समझौता केवल उद्योग की जरूरत नहीं, बल्कि सामरिक आवश्यकता है। विश्व में रेयर अर्थ उत्पादन पर चीन का लगभग एकाधिकार रहा है। भारत लंबे समय से निर्भरता कम करने की रणनीति पर काम कर रहा है। संदेश स्पष्ट है कि भारत अपने औद्योगिक और सामरिक भविष्य को किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं छोड़ेगा। इस साझेदारी से भारत को कच्चे माल की सुरक्षा, नई तकनीक, निवेश और बाजार मिलेगा। ब्राजील को भारत की तकनीकी दक्षता, औषधि आपूर्ति, डिजिटल ढांचा और विशाल उपभोक्ता बाजार का लाभ मिलेगा। यह समझौता एक रणनीतिक घोषणा है कि भारत जहां अपने दोस्तों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, वहीं किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। यह समझौता अमेरिका और चीन के लिए भी बड़ा संदेश है।

लैंगिक समानता की ओर न्यायपालिका का आत्ममंथन

नजरिया

नृपेन्द्र अभिषेक नृप

लेखक शोधार्थी हैं।

न्याय केवल विधि की धाराओं में सीमित शब्दों का संयोजन नहीं, बल्कि समाज की आत्मा में बसने वाला विश्वास है। जब कोई पीड़ित अन्याय की अंधेरी सुरंग से गुजरता है, तो उसे अदालत की चौखट पर ही उम्मीद की पहली किरण दिखाई देती है। विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में न्याय की संवेदनशीलता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि निर्णय की भाषा में करुणा और दृष्टि में निष्पक्षता न हो, तो न्याय अधूरा रह जाता है। अदालतें संविधान की मर्यादा, निष्पक्षता और इस विश्वास का प्रतीक हैं कि कानून का शासन किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह या प्रभाव से ऊपर रहेगा।

न्यायाधीशों पर यह गंभीर दायित्व होता है कि वे कानून की सही व्याख्या करें, उसे ईमानदारी से लागू करें और यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित को न्याय मिले। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे बिना किसी भय या पक्षपात के न्याय करें। किंतु हाल के वर्षों में विशेष रूप से महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से जुड़े कुछ मामलों में न्यायालयों की कुछ टिप्पणियाँ और फैसले सार्वजनिक चर्चा और चिंता का विषय बने हैं। इन घटनाओं ने यह प्रश्न खड़ा किया है कि कहीं न्यायिक सोच में अनजाने पूर्वाग्रह, पितृसत्तात्मक धारणाएँ या लैंगिक संवेदनशीलता की कमी तो प्रभाव नहीं डाल रही। इस बारे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालिका के भीतर अधिक संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया है, विशेषकर यौन हिंसा और लैंगिक अपराधों से जुड़े मामलों में।

सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी एक महत्वपूर्ण सत्य को सामने लाती है कि न्याय केवल कानून की धाराओं को यांत्रिक ढंग से लागू कर देने से नहीं मिलता। न्याय इस बात पर भी निर्भर करता है कि न्यायाधीश किस दृष्टि से मामले को देखते हैं, किस भाषा का प्रयोग करते हैं और किस संवेदना के साथ निर्णय देते हैं। जब अदालतें यौन उत्पीड़न या घरेलू हिंसा जैसे मामलों में कानून की व्याख्या करती हैं, तब उनके शब्द केवल कानूनी टिप्पणी नहीं होते, बल्कि उनका सामाजिक और नैतिक प्रभाव भी गहरा होता है। न्यायालय की एक असंवेदनशील टिप्पणी समाज में प्रचलित गलत धारणाओं को मजबूत कर सकती है, पीड़िताओं को न्याय मांगने से हतोत्साहित कर सकती है और न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कम कर सकती है।

इसके विपरीत यदि न्यायिक दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण और समझ से भरा हो, तो वह संस्थाओं में विश्वास बढ़ाता है और पीड़िता की गरिमा को सम्मान देता है। इसी उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को निर्देश दिया है कि वह विशेषज्ञ समिति गठित कर ऐसे दिशा-निर्देश तैयार करे, जो न्यायाधीशों में यौन हिंसा और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और सहानुभूति विकसित कर सकें।

ऐसी पहल की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि न्यायिक भाषा और तर्क में कई बार पितृसत्तात्मक सोच और पुराने सामाजिक पूर्वाग्रह झलकते रहे हैं। वर्ष 2023 में एक पुस्तिका भी तैयार की गई थी, जिसका उद्देश्य न्यायाधीशों को यह समझाना था कि वे अपनी भाषा में छिपी रूढ़िवादी और स्त्री-विरोधी अभिव्यक्तियों को पहचानें और उनसे बचें। इस पुस्तिका का मकसद यह था कि अदालतें ऐसा मंच न बनें, जहाँ पीड़िताओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोषी ठहराया जाए या उन्हें शर्मिंदा किया जाए। हालांकि यह प्रयास सराहनीय था, लेकिन उसका व्यापक और ठोस प्रभाव अभी तक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया। समय-समय पर ऐसी टिप्पणियाँ सामने आती रही हैं, जिनमें यौन हिंसा को हल्का करके देखा गया या पीड़िता के चरित्र पर प्रश्नचिह्न लगाए गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल दस्तावेज तैयार कर देने से बदलाव नहीं आता, बल्कि निरंतर प्रशिक्षण, जागरूकता और संस्थागत सुधार की आवश्यकता होती है।

लैंगिक हिंसा से जुड़े मामले इसलिए भी जटिल होते हैं क्योंकि वे एक ऐसे सामाजिक ढाँचे के भीतर घटित होते हैं, जो लंबे समय से पितृसत्तात्मक सोच से प्रभावित रहा है। भारत सहित अनेक समाजों में महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर कई प्रकार की असमानताओं का सामना करती हैं। उनकी स्वतंत्रता पर अनकहे बंधन लगाए जाते हैं और उनसे विशेष प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। यदि न्यायिक निर्णय देते समय इन सामाजिक वास्तविकताओं को ध्यान में न रखा जाए, तो कानून की व्याख्या अनजाने में समाज की प्रचलित मानसिकता को ही दोहरा सकती है, जबकि अदालतों से अपेक्षा की जाती है कि वे संविधान के मूल्यों समानता, गरिमा और न्याय, के आधार पर निर्णय दें। यह भी सच है कि न्यायाधीश भी उसी समाज का हिस्सा होते हैं, जहाँ ये पूर्वाग्रह मौजूद हैं। इसलिए यदि वे स्वयं सजग प्रयास न करें और उन्हें व्यवस्थित प्रशिक्षण न मिले, तो ये पूर्वाग्रह अनजाने में उनके निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

अब वक्त आ गया है कि हम यह समझें कि न्यायिक संवेदनशीलता का अर्थ यह नहीं है कि कानूनी मानकों से समझौता किया जाए या साक्ष्यों की कसौटी को ढीला किया जाए। इसका अर्थ केवल इतना है कि न्यायाधीश पीड़िता की मनोवैज्ञानिक स्थिति, उसके सामाजिक परिवेश और उसके सामने मौजूद चुनौतियों को समझें। उदाहरण के लिए, कई बार यौन हिंसा की शिकार महिलाएँ सामाजिक बदनामी, भय या अविश्वास के कारण तुरंत शिकायत दर्ज नहीं करातीं। यदि अदालतें इस देरी को झूठ का संकेत मान लें, तो वे उस मानसिक आघात और सामाजिक दबाव को नजरअंदाज कर देंगी, जिनसे पीड़िता गुजरती है। इसी तरह पीड़िता के पहनावे या उसके निजी जीवन पर प्रश्न उठाना उन रूढ़ियों को बढ़ावा देता है, जो अपराध की जिम्मेदारी को आरोपी से हटाकर पीड़िता पर डाल देती हैं। एक संवेदनशील न्यायिक दृष्टिकोण इस बात को सुनिश्चित करता है कि निर्णय का केंद्र आरोपी की कार्रवाई और कानून के प्रावधान हों, न कि पीड़िता के चरित्र पर नैतिक टिप्पणी।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रशिक्षण और दिशा-निर्देशों की आवश्यकता पर दिया गया जोर समय की मांग है। लैंगिक संवेदनशीलता से जुड़े नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यायाधीशों को बदलते कानूनी मानकों, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सिद्धांतों और मनोविज्ञान के नवीन अध्ययनों से परिचित करा सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों और विधि विशेषज्ञों द्वारा संचालित कार्यशालाएँ न्यायाधीशों के दृष्टिकोण को व्यापक बना सकती हैं और उन्हें आत्ममंथन के लिए प्रेरित कर सकती हैं। ऐसे प्रशिक्षण को किसी की क्षमता पर प्रश्नचिह्न के रूप में नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की मजबूती के निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए।

सुधार का एक महत्वपूर्ण पहलू न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना भी है। जब न्यायपीठ में विविध अनुभव और दृष्टिकोण शामिल होते हैं, तो निर्णय अधिक संतुलित और व्यापक बनते हैं। महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति न्यायिक संस्कृति को अधिक समावेशी बना सकती है। यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि महिला होने से ही संवेदनशीलता स्वतः आ जाए, फिर भी विविधता से निर्णय प्रक्रिया समृद्ध होती है और सामाजिक यथार्थ को समझने में मदद मिलती है। इसलिए न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना केवल प्रतीकात्मक कदम नहीं, बल्कि न्याय की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने का साधन है।

जरूरी है कि संवेदनशीलता केवल अंतिम निर्णय तक सीमित न रहे, बल्कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया में दिखाई दे। गवाही दर्ज करने का तरीका, जिरह के दौरान पूछे गए प्रश्न, और अदालत का वातावरण, ये सभी तत्व पीड़िता को सशक्त भी कर सकते हैं और उसे पुनः आघात भी पहुँचा सकते हैं। अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यवाही के दौरान पीड़िता की गरिमा सुरक्षित रहे, उसकी निजता का सम्मान हो और अनावश्यक या अपमानजनक प्रश्नों से बचा जाए। न्यायिक अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे ऐसी रणनीतियों को रोकें, जिनका उद्देश्य तथ्यों के बजाय चरित्र हनन करना हो।

न्यायालयों के निर्णय समाज पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। वे केवल एक मामले का निपटारा नहीं करते, बल्कि समाज को दिशा भी देते हैं। यदि न्यायालय प्रगतिशील और संवेदनशील व्याख्या अपनाते हैं, तो वे यह संदेश देते हैं कि कानून महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। इसके विपरीत असंवेदनशील टिप्पणियाँ समाज में गलत संदेश पहुँचा सकती हैं और लैंगिक न्याय की दिशा में हुए प्रयासों को कमजोर कर सकती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका पर यह विशेष जिम्मेदारी है कि वह संविधान में निहित समानता और गरिमा के मूल्यों की रक्षा करे।

सर्वोच्च न्यायालय की यह पहल न्यायपालिका के भीतर आत्मचिंतन की भावना को दर्शाती है। पूर्वाग्रह की संभावना को स्वीकार करना ही उसे दूर करने की पहली सीढ़ी है। प्रशिक्षण, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और विविधता को बढ़ावा देकर न्यायपालिका स्वयं को अधिक सक्षम और उत्तरदायी बना सकती है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सच्चा न्याय केवल कानून की धाराओं का पालन करने से नहीं मिलेगा, बल्कि उसमें सहानुभूति, समझ और सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने का साहस भी आवश्यक है। यदि न्यायपालिका इस दिशा में निरंतर प्रयास करती है, तो वह न केवल अपने निर्णयों की गुणवत्ता बढ़ाएगी, बल्कि लोगों के विश्वास को भी मजबूत करेगी कि अदालतें सचमुच न्याय और मानव गरिमा की अंतिम संरक्षक हैं।

पूंजी, प्रकृति और नीति, जलवायु न्याय की तलाश

केंद्रीय बजट

राज कुमार सिन्हा

लेखक बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ से जुड़े हैं।

पर्यावरण के साथ पूंजी के संबंध मामले में पहले की तमाम बुराइयां आज उन क्षेत्रों में प्रकट हो गयी है जिन्हें आमतौर पर 'पर्यावरण संकट' कहते हैं, जिसके अंतर्गत ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन सतह का ध्वंस, उष्णकटिबन्ध के जंगलों का विनाश, मछलियों का बेतहाशा मरना, प्रजातियों का विलोप,जैव विविधता का नुकसान, वातावरण और भोजन में घुलता जहर,मरूस्थलीकरण, जलापूर्ति का सिकुड़ना, साफ पानी का अभाव और रेडियो एक्टिव प्रदुषण शामिल हैं। इसलिए पर्यावरण संबंधी जिन दशाओं के मानव समाज पर सर्वाधिक प्रत्यक्ष प्रभाव पडते हैं,उनको लेकर आर्थिक विकास की योजना इस तरह बनाने की जरूरत होती है ताकि उसमें जल संसाधन और उनके विस्तार, साफ पानी की उपलब्धता, संसाधनों का वितरण और संरक्षण, कचरे का निबटारा तथा आबादी और औधौगिक परियोजना के लिए चुने गये विशेष स्थान से संबंधित पर्यावरण प्रभाव जैसे कारकों को देखते हुए बजट बनाना ज्यादा प्रासंगिक है।

बजट केवल आंकड़े और योजनाएं प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि वे विकास की एक गहरी अवधारणा को भी प्रतिबिंबित करती है कि विकास क्या है और देश आर्थिक वृद्धि कैसे हासिल करना चाहता है। बजट आवंटन इस बात को दर्शाता है कि किन चीजों को महत्व दिया जाता है, किसके हितों की रक्षा की जाती है और विकास की पारिस्थितिकी लागत कौन वहन करता है। ऐसे समय में जब जलवायु संकट, पर्यावरण का क्षरण और सामाजिक असमानताएं बढ़ती जा रही है, बजट का पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण करना आवश्यक है। भारत जैसे तेजी से विकसित हो रहे देश के लिए पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दो ऐसे लक्ष्य हैं जिनका संतुलन रखना आज सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुका है।

विकास कार्यक्रम, बुनियादी ढांचा, रोजगार सृजन और आर्थिक वृद्धि पर ज़ोर देना आवश्यक है, परंतु इसके साथ-साथ पर्यावरणीय स्थिरता और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश भौगोलिक दृष्टि से भारत का केंद्रीय राज्य है, जिसकी अर्थव्यवस्था कृषि, वन एवं खनिज संसाधनों पर आधारित है। राज्य में सूखा, अनियमित मानसून, बाढ़, हीट वेव और जंगल में आग जैसी घटनाएं जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष संकेत हैं। अतः 2026-27 का बजट केवल आर्थिक दस्तावेज न होकर जलवायु-जोखिम प्रबंधन का नीति-पत्र भी होना चाहिए था। मध्यप्रदेश सरकार ने 2026-27 का 4,38,317 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है।पर्यावरण संरक्षण के लिए मात्र 31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के 39 करोड़ रुपए से लगभग 20 प्रतिशत कम है। बजट में सौर ऊर्जा, हरित ऊर्जा निवेश, ई-वाहन प्रोत्साहन जैसे उपायों पर जोर है।परंतु सूखा-प्रबंधन, वर्षा जल-संचयन, जलग्रहण विकास, जल-सरंक्षण आधारित कृषि, और जलवायु-लचीली फसलों पर व्यय तुलनात्मक रूप से कम दिखता है। जबकि राज्य की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। जलवायु जोखिमों के अंतर्गत बुंदेलखंड में सूखा, नर्मदा-घाटी में बाढ़,आदिवासी क्षेत्रों में वन क्षरण के अनुसार बजट में स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

बजट में वनीकरण, कैंपा फंड उपयोग और वन्यजीव संरक्षण के प्रावधान तो हैं, लेकिन सामुदायिक वन प्रबंधन और ग्राम सभा आधारित संरक्षण पर अपेक्षित जोर नहीं है। खनन और अवसंरचना परियोजनाओं को दी गई प्राथमिकता वनों पर दबाव बढ़ाएंगी। विकास प्रधान मॉडल और पारिस्थितिकी संरक्षण के बीच संतुलन स्पष्ट नहीं दिखता है।नर्मदा, ताप्ती, बेतवा जैसी नदियों के पुनर्जीवन कार्यक्रमों की घोषणा सकारात्मक पहल है। परंतु बड़े बांधों और नहर परियोजनाओं पर अधिक खर्च, छोटे जल-संरक्षण मॉडल जैसे तालाब, चेक-डैम, परंपरागत जल संरचनाएं की तुलना में ज्यादा है। विकेंद्रीकृत जल प्रबंधन के बजाय केंद्रीकृत ढांचे पर निर्भरता जलवायु लचीलापन कम कर सकती है। जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के लिए विशेष बजटीय संरक्षण का अभाव है। बजट में स्मार्ट सिटी और शहरी अवसंरचना पर व्यय है, परंतु शहरी हरित क्षेत्र, जल निकासी सुधार और हीट एक्शन प्लान के लिए पृथक आवंटन स्पष्ट नहीं है। जब प्रदेश में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चरम मौसम की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। प्रदेश में बढ़ते तापमान के कारण 2050 तक गेहूं उत्पादन में 6 से 23 प्रतिशत तक की गिरावट हो सकती है। 2023 की तुलना में 2024 में गेहूं उत्पादन 33 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई, जो भारत में सबसे अधिक है। इसे नियंत्रित करने के लिए प्रभावी और ठोस कार्ययोजना का बजट में अभाव है।

दूसरी ओर केंद्रीय बजट 2026-27 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को लगभग 3,759.46 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत अधिक है। पर विशेषज्ञों के अनुसार यह अभी भी भारत के विशाल पर्यावरणीय जोखिमों और आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त नहीं है। केंद्रीय बजट बुनियादी जीवाश्म ईंधन, खनन, और पारंपरिक अवसंरचना पर बजट में भारी ध्यान है, जबकि पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी लागतों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। उच्च-कार्बन उद्योगों से आर्थिक निर्भरता हटाने में बजट कदम पर्याप्त नहीं हैं और अभी भी पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर भारी निवेश हो रहा है। बजट का एक बड़ा हिस्सा 'बड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर' पर केंद्रित है,यानी राजमार्गों, शहरों, बंदरगाहों और अन्य बड़े ढांचागत परियोजनाओं पर भारी खर्च करने का है। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार सृजित होंगे और अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। लेकिन जो बात अक्सर छूट जाती है, या जानबूझकर उल्लेख नहीं की जाती है। वह है इन परियोजनाओं का पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव। केंद्र की आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि विकास परियोजनाओं के लिए वन स्वीकृतियां एक बाधा है, जबकि व्यवहार में सरकार द्वारा स्वीकृतियां अक्सर तेजी से दी जाती है।

कुल मिलाकर, बजट ने अवसंरचना को इस तरह बढ़ावा दिया मानो उसके पारिस्थितिक और सामाजिक प्रभाव महत्वहीन हों। जब जंगलों को बाधा के रूप में देखा जाता है, जब सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के बजाय लग्जरी ट्रेनों पर जोर दिया जाता है और जब समुद्री तटों को निजी कंपनियों को सौंप दी जाती हैं, तब हम केवल निर्माण नहीं कर रहे होते हैं बल्कि हम पर्यावरण और समुदायों को जोखिम में डाल रहे होते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण ने यह स्वीकार किया गया है कि केवल 37 प्रतिशत शहरी आबादी को सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध है, लेकिन बजट में इसे सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं दिखता है। शहरों की कल्पना कारों और हवाई अड्डों से भरे भविष्य के रूप में की जा रही है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान (नीरी) नागपुर ने अपने अध्ययन में बताया है कि देश की 30 प्रतिशत भूमि में उत्पादकता समाप्त हो गई है।

इसलिए किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित करने के लिए निवेश की जरुरत है। जबकि कृषि बजट उर्वरक सब्सिडी पर केंद्रित रहता है। स्वस्थ भूमि संपन्न अर्थव्यवस्थाओं का आधार है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का आधा से अधिक हिस्सा प्रकृति पर निर्भर है। फिर भी हम इस प्राकृतिक पूंजी को खतरनाक दर से नष्ट कर रहे हैं। इससे जैव विविधता का नुकसान होता है, सूखे का खतरा बढ़ता है और समुदाय विस्थापित होते हैं। मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा हमारे समय की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। जलवायु संकट से निपटने के लिए कोई ठोस रणनीति प्रस्तुत नहीं करता है। सरकार को चाहिए कि वह एक स्पष्ट बजट लाइन, समर्पित वित्तीय रणनीति और विभागीय समन्वय सुनिश्चित करे, ताकि जलवायु कार्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और कमजोर समुदायों को सुरक्षा प्रदान की जा सके।

सड़क के गड्ढे की आत्मकथा

कटाक्ष

दिनेश विजयवर्गीय

लेखक व्यंग्यकार हैं।

जैसे मनुष्य जीवन में जन्म के साथ मृत्यु और सुख के साथ दुख जुड़े हुए हैं, वैसे ही सपाट चिकनी सड़क के साथ गड्ढे भी जुड़े हुए हैं। हर शहर के सड़क की आत्मा में गड्ढे अनुकूल स्थिति पाकर सहज ही स्थान पा लेते हैं। जैसे वाटिका में रंग बिरंगी फूल अपने होने को गौरवान्वित समझते हैं, वैसे ही गड्ढे भी अपने को चिकनी सपाट सड़क पर गौरवान्वित समझते हैं।

लेकिन सड़क के गड्ढे अपना जीवन सुख शांति से नहीं गुजारना चाहते । समय पर वह अपनी प्रभावी उपस्थिति जताने के लिए लोगों की हड्डी पसली तोड़कर रख देते हैं ।इतना ही नहीं कभी तो वह इतनी शातिर ढंग से व्यक्ति के यात्रा में जुड़े रहते हैं कि उसे घायल कर उसके जीवन को ही बैकुंठ धाम पहुंचा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही झील किनारे की एक सुनसान सी रहने वाली सड़क के गड्ढे ने इतना कहर बरपाया कि एक मोटरसाइकिल सवार पति-पत्नी और उनके पुत्र न सिर्फ घायल हुए पति और बच्चे की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। बेचारी पत्नी चीखती चिल्लाती रही। उसका हरा भरा जीवन रेगिस्तान की तरह सूखा वीरान होकर रह गया। तीन दिन पूर्व एक तेज स्पीड कार रात्रि के समय अचानक इसी गड्ढे के सामने आने और फिर इससे बचने के चक्कर में पलट गई। कार सवार बुरी तरह घायल होगये।

गड्ढों की हिंसात्मक खबरें सुनकर मैंने अपने अखबार के लिए उससे बातचीत करने का मन बनाया । मैं एक दिन शाम के समय स्कूटी से उस रोड की ओर ही घूमने निकल गया। मैं जब पहुंचा तो उस समय वहां लोगों की आवाजाही नहीं के बराबर थी । मैंने अपनी स्कूटी उस गड्ढे के दूर सड़क किनारे खड़ी की और पेन डायरी लेकर उसके पास पहुंच गया । गड्ढा मुझे देख इस तरह बोला जैसे उसे पता हो कि मैं पत्रकार हूं और वह जैसे अपनी बात कहने के लिए तैयार बैठा हो। मैंने पूछा 'तुम्हारा चिकनी सपाट सड़क पर होना तुम्हें बुरा नहीं लगता ? ऐसा लगता है जैसे मीठा खाते-खाते नीम के पतियों चबाली हो या सफेद दीवार पर काली रेखा खींचदी हो।' वह बोला 'अब तुम्हें मेरे बारे में जो संभावित जानकारी चाहिए उसे आगे होकर मैं ही बता देता हूं।' लगा जैसे गड्ढा पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर देने में माहिर हो। उसने अपनी बात कहना शुरू किया। 'मेरी आदत दूसरों की खुशी में कोई रुकावट डालने की नहीं है। लेकिन मैं भी क्या करूं ? मुझे सड़क पर गड्ढा रूप थोड़े ही अच्छा लगता है। आने जाने वालों की बद्दुआएं झेलनी पड़ती हैं। इतना ही नहीं कभी तेज गति से आ रहे वीकल्स अचानक मुझे देख बचने के चक्कर में गिरकर लहू लुहान हो जाते हैं । कई का तो जीवनी ही देखते ही देखते समाप्त हो जाता है। कभी तेज गति की कार सड़क के सब जगह के चिकनी होने के भ्रम में जब अचानक मुझे देखती हैं तो तेजी से ब्रेक लगाते हैं। इसके चलते संतुलन बिगड़ने से कार पलटी मार लेती है । फिर क्या कुछ अप्रिय होगा पूछो मत। कभी तो लोग घायल हो जाते हैं। कभी लोग मारे जाते हैं और कभी कार में आग लग जाती है। मैं सच में दुखी हूं । मुझे हत्यारा होने का तमगा लोगों द्वारा पहना दिया जाता है। पर इन सबके लिए मैं बिल्कुल भी गुनहगार नहीं हूं । जब मेरी जन्मदात्री , सड़क मां का निर्माण ही घटिया माल लगाकर हुआ है तो बताओ मैं ऐसे में सड़क या मुझे दोष देना कहां तक उचित है? जिम्मेदार लोगों ने कमीशन के चक्कर में कोई ध्यान न देकर, सब कुछ ठेकेदार के भरोसे छोड़ दिया । सड़क निर्माण कार्य को ना कोई देखने वाला ना सुनने वाला । उसे तो बस ऐसा आनंद आगया, जैसे मामा के घर में मां परोसने वाली मिल जाए । मेरी क्षमता अधिक भार सहने की नहीं है।

इसलिए जहां में थोड़ी अधिक कमजोर होती हूं वहीं मेरा जन्म होने लगता है। और फिर रही सही कसर बारिश पूरा कर देती है। पानी भरने लगता है। मेरा आकार धीरे-धीरे विस्तारित होने लगता है।'

'जब कभी लोग मेरी टूट फूट की शिकायत करते हैं तो जिम्मेदार विभाग मेरे ऊपर डामर रेत गिट्टी से लीपापोती करके अपनी जिम्मेदारी पूरा कर देता हैं। जबकि इस पेंचवर्क में भी वही घटिया सामग्री लगा दी जाती है इसलिए कुछ ही दिनों में इस भ्रष्ट काम की पोल खुल जाती है । '

' पत्रकार महोदय ! आपने मेरी दुखती नस पर हाथ रख, दिल की बात पूछी है । इसके लिए आपको धन्यवाद। अब जरा मेरी पीड़ा अखबार से प्रकाशित होगी तो लोग मुझे दोष न देकर जो मेरे इस अप्रिय रूप के लिए जिम्मेदार हैं, उनके बारे में जनता जान सकेगी।' मैने गड्ढे से उसकी दिल की बात सुनी और फिर उसका एक फोटो लेकर प्रेस के लिए रवाना हो गया।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

बोलने वारे के तो बेर भी बिक जात हैं

व्यंग्य

सुधीर देशपांडे

लेखक व्यंग्यकार हैं।

अम्मा ने कई थी के 'बोलियो मती।' पर मोड़ा ने कई - 'अम्मा तुम हमसे ऐसो न कओ। एक दफे तो तुमई ने कहानी सुनई थी जाको सार थो- बोलने वारे के तो बेर भी बिक जात हैं। गूँगे से कोई कछु न खरीदे। सच्ची के रए, जोन बड़ी जगे पे जानो होए तो बोलने को अभ्यास भी होनो चईए।' पप्पू ने कहा। 'भैया, हमने तो जे भी कई थी के जब बोलना बनेई नहीं तो चुप व्है जाओ तो वाको समझदारी कहत है। सुनें नई का सबसे भली चुप।' 'पर अम्मा, कोई कछु बोलत हैं तो हमसे चुप न रहे जात है।' पप्पू बोले। 'तो जरूरी है का, कि अपन बोलोई? जग हंसाई होत है वाको का? मोड़ी देखबे गए हते तो सारे घरई की पोल पट्टी खोल के आ गए। कछु समझ नइया। तुमई ने नई कई की तुमने दसवीं की परीक्षा में नकल करी हती। फिर भी पास नहीं भये। जबकि हमने तो तुम्हें लड़की वाले के बारवीं पास बताओ तो। कमाई कित्ती करत है तो हमने की थी, अच्छी हे तो तुमाए मू में कीड़ा पडे, बताए आए कछु ना कमा रए। और तुमसे गाने की किनने कई थी। ऐ..!' अम्मा कुछ खीज कर बोली। 'अब तुमने कछु सीखोई नई तो काहे गाना गाए आए। बताए आए के हमाएई घर में तानसेन के बब्बा पैदा भए हते। चलो गा लओ तो ठीक, पर सूर मूर तो मिला लेते। न मिलो सुर तो कछु बात नई, बोलई सई बोल देते। सबरी भद पीट दई। अब तुमाए घर में भलेई तानसेन के बब्बा पैदा हो जाएं, पर तुम तो तानसेन नई बन पाए न।' अम्मा अब चिढ़ कर बोली थी। - 'अब तुमई देखो, तुम्हाए बब्बा, बिना बोले ही काम कर गए की नई। इते कछु करन जात हो, कछु और कर के आ जात हो। अब जे बताओ तुम घर से बार बार बाहर काए भाग जाते हो। भाग के कौनों बगीचा में बैठ गए जे नई, दस लोगन के बीच में खड़े होके अपनेई महतारी बब्बा के बारे में उल्टा सीधा बोल आए। तुम्हें पता है, मोड़ी बारे मना कर गए- ऐसा नमूना से कौन ब्याहेगो अपनी मोड़ी कह के। खबरदार जो घर के बाहर कदम रक्खे तो।' अम्मा का गुस्सा साफ दिख रहा था। ये एक बार नहीं था। घर के सब लोग परेशान, पर पप्पू सीखे तो। किसी ने कहा था- सीखने की उम्र नहीं होती। सीख लो। अच्छी बात है। बोलना आना चाहिए। अभिव्यक्ति के लिए बोलना जरूरी है और ऐसा थोड़े है कि तुम अकेले ही बोलते रहो। कह रहे थे, बोलने वाले के बेर बिकते हैं।

बताओ अब तक तुमाए किस्तें बेर बिक गये। बिक गये तो पैसा कहाँ है। इसी बात पे बब्बा कई बार ठोक चुके थे। दस लोग सुनते हैं तो हँसते हैं। पप्पू कहते कुछ हैं और लोग मतलब कुछ निकाल लेते हैं। चतुराई भी नहीं पर चतुर समझते रहे। लौंडे लपाटियों को घेर के बैठे रहते हो। जैसे तुम, वैसी तुम्हारी फौज। कुछ काम की न काज की, नौ मन अनाज की। अरे सब नाम मिटा दओ, हर रोज अपने बाप दादा का मूं काला कर रहे। जितना कमाया उससे ज्यादा गमाए आए। अब छोटे न रहे। पचास के पार जाने की तयारी है। अम्मा की तकलीफ़ यही है। सोच के बोलने के लिए कितना कहा, कितनों ने कहा, कितनी बार कहा पर है कि बोलने की झोंक में जो आते कि क्या बोल रहे कुछ समझ न पाते। अम्मा ने इस बार साफ चेतावनी दी- अब देखना कछु बोले तो। पप्पू बोले- तुम कुछ भी कल्लो, मैं तो बोलूंगो।

अनुभव

श्याम बोहरे

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

बदलाव का उजास, हमारी जाति गरीबी है

बात 1981 की है नेहरु युवा केन्द्र होशंगाबाद और किशोर भारती के संयुक्त तत्वाधान में जंगल शिविर आयोजित किया। शिविर का उद्देश्य गांव के लोगों के सहयोग से उनके ईंधन और दैनिक जीवन में लकड़ी की जरुरतों को उनके ही सहयोग से पूरा कर उन्हें इस मामले में आत्मनिर्भर करना था। दस दिन के इस शिविर में गांव के साथियों के साथ तय हुआ कि उनके उपयोग में आने वाले आने वाली लकडी जिन वृक्षों से मिले उनके पौधे लगाए जाएं, गांव वाले इन्हें लगाएं तथा इनकी देखभाल करें, विकसित करें। वे सामूहिक निर्णय से जरुरत के अनुसार आपस में लकड़ी का बंटवारा करेंगे। सत्तर एकड़ जमीन में पौधे लगाए जाएंगे।

सब कुछ तय होने के बाद पलिया पिपरिया गांव के 40 साथियों के साथ शिविर के पहले तैयारी बैठक हुई। भोजन की व्यवस्था शिविर में ही थी। हम गांव के जातिगत समीकरणों से अधिक परिचित नहीं थे मतलब यह कि गांव में काम करने का दंभ भरने के बावजूद हम गांव समाज को अधिक नहीं जानते थे। इसलिये हमें सब कुछ सामान्य लग रहा था। जब भोजन व्यवस्था का मामला आया तो बताया गया कि किस जाति के सदस्य भोजन पका सकते हैं? कौन परोस सकता है? कौन पका हुआ भोजन नहीं छू सकता है? किसके हाथ का छुआ पानी भी नहीं पियेंगे? इतना ही नहीं भोजन करने कौन, कहां बैठ सकता है, कौन किसके पास नहीं बैठेगा, कौन कितनी संधि देकर मतलब कितनी दूरी पर बैठेगा, आदि आदि। वह समय था जब हम सामाजिक बदलाव के सपने देखते थे। कबीर, भगत सिंह, अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, गांधी की विरासत सहेजने का जुनून सिर पर सवार रहता था। गनीमत थी कि इसके लिए हमें कोई अर्बन नक्सल या टुकड़े-टुकड़े गैंग नहीं कहता था। उस माहौल में जातिगत ऊंच-नीच और भेदभाव की इस व्यवस्था को स्वीकार करना कितना तकलीफदेह रहा होगा आज इस अमृतकाल में अंदाज लगाना कठिन है। कोई विकल्प नहीं था। इसलिए मन मारकर रणनीति के तहत इस आचार संहिता को स्वीकार कर लिया गया।

शिविर का कार्यक्रम तय हुआ कि सुबह नाश्ते के बाद पौधारोपण के लिए जमीन की सफाई, गड्ढे करना, गड्ढों में खाद भरना, पौधे लगाना, गड्ढों को मिट्टी से पूरना, सिंचाई करना आदि। दो-तीन दिन तो तयशुदा योजना के अनुसार सब कुछ चला। एक दिन बाहर से आए एक साथी, जिन्हें भोजन के संबंध में आचार संहिता की जानकारी नहीं थी, सहज भाव से परोसने लगे। भोजन कर रहे साथियों ने इस आरोप के साथ हंगामा बरपाया कि उनके साथ धोखा करके धर्म भ्रष्ट करने की तरकीब है, जिसे चे मान ही नहीं सकते। भोजन का बाकायदा बहिष्कार किया गया। लगभग दो घंटे की माथापच्ची, आरोप-प्रत्यारोप, मान मनोव्वल और अंत में माफी मांगने के बाद, आचार संहिता और सख्त करते हुए देर रात तक किसी तरह मामला शांत हुआ।

इस घटना के दूसरे दिन सुबह जब काम शुरु हुआ, उसके करीब दो घंटे बाद सभी साथी जुलूस की शक्ल में नारे लगाते हुए काम छोड़ कर चले आ रहे थे। हमारा माथा ठनका कि रात में मुश्किल से हुई रजामंदी के बाद यह कौन सा नया बखेड़ा खड़ा हो गया? जुलूस के पास आते ही चिंता सुखद आश्चर्य में बदल गई, जब उनका नारा सुना 'हमारी जाति गरीबी है।'

साथियों ने बताया कि हरि भाई ने आज हमारी आंखें खोल दीं। हरि प्रसाद जोशी से पूछा कि यह कैसे हुआ? हरि भाई ने कहा, इन्हीं से पूछो। साथियों ने बताया कि हरि भाई आज बहुत दुखी थे। वे बोले इस शिविर का कोई मतलब नहीं। इसे अभी खत्म कर देते हैं। साथियों ने उनसे पूछा कि रात में सब कुछ निपट तो गया। अब ऐसी बात काहे कर रहे हो? हरि भाई ने तो एक के बाद सवालों की झड़ी लगा दी। हम यह सब किस लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? इससे क्या हो जाएगा? साथियों के यह कहने पर कि संगठन बना कर अपनी परेशानियों से लड़ने के लिए। क्या तुम्हें नहीं मालूम? हरि भाई ने कहा जब तक हम आपस में बंटे रहेंगे तो संगठन कैसे बनेगा? हम एक साथ बैठकर रोटी तो खा नहीं सकते बड़े आए संगठन बनाने। जातियों में बंटे रहेंगे फिर भी संगठन बना लेंगे?

ग्रामीण सोच-सोच कर एक सवाल का उत्तर दे पाते हरि भाई दूसरा सवाल कर देते। कहते सोचो जरा ये जातियां बनाई किसने? क्यों बनाई? इससे किसको फायदा है? किसको नुकसान है? जब उनसे पूछो तो कहते खुद सोचो, किसी बात का उत्तर न देते। हम जो भी कहें वे बड़े प्यार से मुस्कराते हुए फिर सवाल कर देते। कुछ भी पूछो बस एक ही बात, सोचो... सोचो। सोच कर बताओ कोशिश करो। यह समस्या हमारी तो है नहीं तो हम इसका हल कैसे बता सकते हैं? कांटा तुम्हारे पांव में लगा है। तुम्हारे पांव का कांटा तुम ही निकाल सकते हो। कोई दूसरा नहीं आएगा तुम्हारे पांव का कांटा निकालने।

एक साथी ने कहा, हरि भाई ठीक तो कह रहे हैं जो मिलकर नहीं रहते वे भुगतते है। धीरे-धीरे बात समझ में आने लगी। जहां समझ में न आया वहां गाड़ी रुकने लगे। हरि भाई नया सवाल करके धक्का लगा देते। जैसे-जैसे बात समझ में आने लगी, सभी को उसमें रस आने लगा। जब बहुत कुछ साफ हो गया तो हरि भाई ने पूछा, अब बताओ तुम्हारी जात क्या है? लछ्मन दादा बोले, 'हमारी जात गरीबी है।' यह सुनते ही हरि भाई ने लछ्मन दादा को गले से लगा लिया। हरि भाई की आंखें में आंसू आ गए। वे बोले, आज से लछ्मन दादा हमारे गुरु। सबने जोश में आकर जोरदार नारे लगाए, हमारी जात गरीबी है, हमारी जात गरीबी है।

किसी ने याद दिलाया कि बहुत हो गई नारेबाजी चलो काम शुरु करो। एक साथ कई साथी बोले, बहुत बड़ा काम हो गया। चलें सभी को खुशखबरी दें और वे नारे लगाते हुए आ गये हम सब को बताने। इससे अधिक सफलता किसी भी कार्यक्रम की और क्या हो सकती है? बड़ी बात यह रही कि शिविर के बाद कई परेशानियों के बावजूद भी साथी अपने फैसले पर डटे रहे। गांव के बाकी लोग जो शिविर में नहीं थे, इस फैसले को आसानी से पचा नहीं पा रहे थे। कई दिनों तक बहस चलती रही। गांव में ही नहीं, आसपास के रिश्तेदारों में भी। लेकिन शिविर में भाग लेने वाले साथी अपनी बात पर डटे रहे। शिविर के बाद उनके संगठन में मजबूती आने लगी। बहुत ही लगन के साथ लगाये गये पौधों की देखरेख की जाने लगी। कुछ साल बाद पौधों के बड़े होने पर काम की कुछ लकड़ी निकाली जाने लगी, जो बहुत ही समझदारी से आपस में बांटी जाने लगी।

जातिगत भेदभाव मिटाने की कई तरह की कोशिशें की जाती हैं। उनका असर भी होता हैं। जंगल शिविर के इस अनुभव से जो भी सीख मिली उसके सबक जानने से पहले कुछ बातें जानना जरुरी होगा वरना प्रक्रिया का सरलीकरण हो सकता है।

1. किशोर भारती संस्था का वहां 10 साल से ग्रामीण विकास और शिक्षा के काम करते रहना, संस्था के कार्यकर्ताओं की समझदारी, नियत और प्रतिबद्धता में गांव वालों का भरोसा, संस्था द्वारा किये गये कामों के लाभ मिलते रहना, जिसके कारण आपस में संवाद और भरोसा था।

2. यद्यपि औपचारिक स्तर पर शिविर सरकार के कार्यालय द्वारा आयोजित था, लेकिन गांव वाले उसे किशोर भारती का ही काम समझते थे। यद्यपि मैं भारत सरकार में जिला स्तर का अधिकारी था ,लेकिन किशोर भारती से और उनके माध्यम से गांव वालों से मेरे संबंध अनौपचारिक, सरल और दोस्ताना थे। इसका मुझे भरपूर फायदा मिलता रहा। यह मैं इसलिए कह सकता हूं कि जिले के 11 विकासखण्डों में काम करता था लेकिन किशोर भारती के प्रभाव क्षेत्र में काम का जो असर था वह दूसरे क्षेत्रों में दूर दूर तक नहीं था। हो भी नहीं सकता था।

सीखे गए सबक को इस तरह कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन लंबे समय की प्रक्रिया है, जो कुछ कार्यक्रमों मात्र से शायद न हो। परिवर्तन किसी एक कारण से नहीं होता। अनेकों कारण, काम, घटनाओं और सामाजिक- राजनीतिक परिस्थितियों के मेल से यह हो पाता है। अक्सर कई तरह के परिवर्तन होते रहते हैं लेकिन कौन कितना टिकाउ होगा और किस वजह से हुआ, यह कहना आसान नहीं है। भरोसा हो तो सतत रुप से गंभीर कोशिश करते रहने से बात बनती है। यह समझना भी जरुरी है कि भरोसा बातों से नहीं काम के नतीजे देखकर होता है।

समाज का अर्थशास्त्र

ब्रजेश कानूनगो

लेखक स्तंभकार हैं।

घाना के बाजार : महिला सशक्तिकरण की मिसाल

विश्वभर में कई समुदायों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था प्रचलित है, जहाँ वंश, संपत्ति और निर्णय लेने का अधिकार महिलाओं के पास होता है। प्रमुख रूप से जिनमें इंडोनेशिया के मिनांगकाबाऊ, चीन के मोसुओ जनजाति, और भारत के मेघालय की खासी जनजाति भी शामिल हैं। इन समाजों में महिलाएँ परिवार की मुखिया और उत्तराधिकारी होती हैं।

जुटाई जानकारी के अनुसार मिनांगकाबाऊ समाज इंडोनेशिया में है जो दुनिया का सबसे बड़ा मातृसत्तात्मक समाज माना जाता है, जहाँ संपत्ति महिलाओं द्वारा हस्तांतरित होती है। मोसुओ, चीन (यूनान और सिचुआन) के मोसुओ समाज को 'महिलाओं का साम्राज्य' कहा जाता है। यहाँ 'वॉकिंग मैरिज' की परंपरा है। भारत के मेघालय की खासी और गारो जनजातियों में वंशावली माँ के नाम से चलती है और सबसे छोटी बेटी (खतदुह) को संपत्ति विरासत में मिलती है। कोस्टा रिका की ब्रिब्री स्वदेशी जनजाति में महिलाएं भूमि की मालकिन होती हैं और कबीले के प्रमुख का पद महिलाओं के माध्यम से चलता है। नासो समुदाय जो पनामा और कोस्टा रिका में है वह भी खुद को मातृसत्तात्मक बताता है। घाना (अफ्रीका) का आसानते भी एक प्रमुख मातृवंशीय समूह है। घाना गणराज्य पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है, जो पूर्व में टोगो, पश्चिम में कोटे डी आइवर, उत्तर में बुरकिना फासो, और दक्षिण में गिनी की खाड़ी से घिरा हुआ है। घाना की राजधानी अकरा है, और यह देश की सबसे बड़ा शहर भी है।

पिछले दिनों हमने यूट्यूब पर एक ट्रैवलर के वीडियो में घाना के एक ऐसे बाजार को नजदीक से देखा जहां बाजार की सारी बागडोर महिलाओं के हाथ में थी। जिन्हें वहां मार्केट क्वीन कहा जाता है। मातृसत्तात्मक समाजों की प्रमुख विशेषता यह होती है कि विवाह के बाद पति पत्नी के घर जाकर रहता है और बच्चों का वंश माँ के परिवार से पहचाना जाता है। लेकिन घाना के मातृसत्तात्मक बाजार की मार्केट क्वीन का इनसे बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। मातृसत्तात्मक समाजों में, महिलाएं परिवार और समुदाय के निर्णयों में भूमिका निभाती हैं और संपत्ति की उत्तराधिकारिता भी महिलाओं के माध्यम से होती है। उदाहरण के लिए, भारत की खासी जनजाति और घाना के अकरन समुदाय में महिलाएं परिवार और समुदाय के निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जबकि घाना की मार्केट क्वीन महिलाएं इन सब के अलावा 'बाजार संचालन' में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को दर्शाता है, न कि मातृसत्तात्मक समाज की विशेषता। ये महिलाएं बाजार में अपनी शक्ति और प्रभाव का उपयोग करती हैं।

घाना में 'मार्केट क्वींस' उन वरिष्ठ और प्रभावशाली महिला व्यापारियों को कहा जाता है, जो बाजारों में विभिन्न कमोडिटी समूहों (जैसे टमाटर, मक्का, या याम) का नेतृत्व करती हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में 'ओहेम्मा' भी कहा जाता है। वे बहुत कुशलता से बाज़ार के विशिष्ट अनुभागों का प्रबंधन करती हैं और व्यापारियों के बीच विवादों को सुलझाती हैं। बाज़ार में आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ ग्रामीण उत्पादकों (किसानों) को शहरी बाज़ारों से जोड़ने के उपाय करती हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ये महिलाएं अक्सर एक अनौपचारिक बैंकिंग प्रणाली के रूप में काम करती हैं, जो छोटे व्यापारियों को ऋण और सहायता प्रदान करती हैं। इस तरह ये महिलाएँ घाना के अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और पारंपरिक रूप से व्यापार को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी निभाती हैं। स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका के साथ बातचीत कर बाजार की सुविधाओं (साफ-सफाई, टैक्स आदि) का प्रबंधन करती हैं।

घाना की अर्थव्यवस्था और वहां के बाजारों की संरचना दुनिया के सबसे दिलचस्प उदाहरणों में से एक है। यहाँ महिलाओं का वर्चस्व है, यहां तक कि बाजार में सिर पर माल ढोने वाली श्रमिक महिलाएं भी बाजार में अपना पसीना बहाते जुटी होती हैं। इन्हें स्थानीय स्तर पर 'कायायेई' कहा जाता है। 'काया' का अर्थ है 'सामान' और 'येई' का अर्थ है 'महिलाएं'। ये ज्यादातर उत्तरी घाना के गरीब इलाकों से बेहतर जीवन की तलाश में दक्षिण के बड़े शहरों (जैसे अकरा और कुमासी) में आती हैं। ये महिलाएं अपने सिर पर बड़े एल्यूमीनियम के परातों में भारी सामान, अनाज की बोरियां और खरीदे गए कपड़े लेकर चलती हैं। इनका जीवन अत्यंत कठिन होता है। वे बहुत ही कम मजदूरी पर काम करती हैं और अक्सर बाजारों के पास खुले में या झोपड़ियों में रहती हैं। घाना की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में इन महिलाओं का योगदान अतुलनीय है। मार्केट क्वींस घाना के व्यापार की रणनीतिकार हैं, तो कायायेई उस व्यवस्था की मांसपेशियां। इन दोनों के बिना घाना की रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था का चलना लगभग असंभव है। घाना की सामाजिक और आर्थिक संरचना में वहां की मातृसत्तात्मक व्यवस्था का बड़ा महत्व हो जाता है। यह व्यवस्था न केवल परिवारों को चलाती है, बल्कि वहां के विशाल बाजारों के स्वरूप को भी निर्धारित करती है।

घाना की सरकार और विभिन्न गैर-सरकारी संगठन इन महिलाओं, विशेषकर 'कायायेई' की स्थिति सुधारने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। चूंकि मार्केट क्वींस पहले से ही प्रभावशाली और आर्थिक रूप से मजबूत हैं, इसलिए सरकारी प्रयासों का मुख्य केंद्र बोझ ढोने वाली श्रमिक महिलाएं ही होती हैं।

कौशल विकास और प्रशिक्षण के अंतर्गत इन महिलाओं को केवल शारीरिक श्रम पर निर्भर रहने से बचाने के लिए 'कायायेई एम्पावरमेंट प्रोग्राम' शुरू किया है। इसमें उन्हें सिलाई, साबुन बनाना, बेकिंग और कंप्यूटर जैसे तकनीकी कौशल सिखाए जाते हैं। ताकि वे बाजारों से निकलकर सम्मानजनक और कम जोखिम वाले व्यवसायों में जा सकें। कायायेई अक्सर खुले आसमान के नीचे या असुरक्षित बस्तियों में सोती हैं। इसे देखते हुए सरकार ने अकरा और कुमासी जैसे बड़े शहरों में इनके लिए विशेष हॉस्टल का निर्माण शुरू किया है। यहाँ उन्हें सुरक्षित रहने की जगह, पानी और स्वच्छता की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सरकार इन महिलाओं का 'नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम' में मुफ्त या रियायती दरों पर पंजीकरण कराती है ताकि बीमारी की स्थिति में उनका इलाज हो सके। अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ी इन महिलाओं को मुख्यधारा की बैंकिंग से जोड़ने के लिए मोबाइल मनी और छोटे बचत खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 2017 में घाना सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कायायेई पर लगने वाले 'मार्केट टोल' (प्रतिदिन का कर) को खत्म कर दिया था। इससे उनकी दैनिक आय में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि पहले उन्हें अपनी मामूली कमाई का एक हिस्सा नगर पालिका को देना पड़ता था। बाजारों में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए 'डे-केयर सेंटर' और स्कूलों में नामांकन की सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि उनकी अगली पीढ़ी को इस कठिन श्रम चक्र से बाहर निकाला जा सके। घाना में अब कई महिलाएं 'मार्केट क्वींस' के नेतृत्व में डिजिटल साक्षरता भी सीख रही हैं ताकि वे व्हाट्सएप और अन्य ऐप्स के जरिए अपने माल का ऑर्डर ले सकें।

घाना के प्रसिद्ध बाजारों (जैसे कि अकरा का मकोला मार्केट) में महिलाओं का वर्चस्व इतना अधिक है कि इसे अक्सर 'मातृसत्तात्मक' आर्थिक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। वहां 'मार्केट क्वींस' न केवल व्यापार बल्कि सामाजिक नियमों को भी नियंत्रित करती हैं।

ऐसे में पुरुषों की भूमिका पूरी तरह से खत्म नहीं होती, बल्कि वह मुख्य रूप से लॉजिस्टिक्स, भारी श्रम और थोक आपूर्ति तक सीमित होती है। घाना के बाजार में एक अनकहा नियम हैः 'महिलाएं व्यापार का चेहरा हैं, और पुरुष उसकी मांसपेशियों (शक्ति) का काम करते हैं।' वहां पैसा और बाजार की राजनीति महिलाओं के हाथ में होती है, जबकि पुरुष उन सेवाओं को प्रदान करते हैं जिनके बिना बाजार चल नहीं सकता।

घाना में बाजार केवल व्यापार का केंद्र नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण की एक जीवित प्रयोगशाला है, जहाँ मातृसत्तात्मक मूल्यों ने महिलाओं को 'शक्ति' और 'पूंजी' दोनों दी हैं।

मुद्दा

ममता कुशवाहा

लेखक शिक्षक हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भारत की जिम्मेदारियाँ

विज्ञान के आविष्कार ने हमारे जीवन को कितना आसान बना दिया है! हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक रोज नए-नए अविष्कार कर रहे हैं। इसी में से एक है एआई का अविष्कार। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) 21वीं सदी की सबसे प्रभावशाली और परिवर्तनकारी तकनीकों में से एक बनकर उभरी है। यह केवल भविष्य की कल्पना नहीं रही, बल्कि आज की वास्तविकता है, जो उद्योगों की संरचना बदल रही है और शासन-प्रणालियों को नए रूप में ढाल रही है। विश्व स्तर पर आयोजित सम्मेलनों और मंचों पर एआई की संभावनाओं पर गंभीर चर्चा हो रही है। ऐसे समय में भारत जैसे देश एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। एआई क्रांति भारत के लिए विकास, नवाचार और वैश्विक नेतृत्व के असाधारण अवसर लेकर आई है, लेकिन इन अवसरों के साथ कई गंभीर चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं, जिनसे निपटने के लिए दूरदर्शी नीति, सुदृढ़ योजना और नैतिक सजगता आवश्यक है।

वैश्विक एआई परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका उसके तकनीकी कौशल और मजबूत डिजिटल ढांचे को दर्शाती है। देश के पास कुशल इंजीनियरों की बड़ी संख्या, सक्रिय स्टार्टअप संस्कृति और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहलें हैं। इसी कारण भारत एआई के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बनने की क्षमता रखता है। अंतरराष्ट्रीय कंपनियाँ भी भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं, क्योंकि वे इसे एक बड़े बाजार और नवाचार के केंद्र के रूप में देखती हैं। किंतु यह वैश्विक आकर्षण प्रतिस्पर्धा और दबाव भी साथ लाता है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह केवल विदेशी तकनीकों का उपभोक्ता न बनकर, स्वयं तकनीक विकसित करने वाला और नवाचार करने वाला देश बने। यदि देश एआई की मूल तकनीकों के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहा, तो इससे उसकी दीर्घकालिक रणनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक मजबूती प्रभावित हो सकती है।

एआई क्रांति की एक प्रमुख चुनौती स्वदेशी तकनीकी क्षमता का विकास है। एआई प्रणालियों के निर्माण के लिए विशाल डेटा, उन्नत कंप्यूटिंग संसाधन और उच्च स्तरीय शोध की आवश्यकता होती है। भारत ने डिजिटल सार्वजनिक ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी उच्च क्षमता वाले कंप्यूटिंग संसाधनों और बुनियादी शोध के क्षेत्र में वह अभी अग्रणी देशों से पीछे है। इस अंतर को कम करने के लिए अनुसंधान और विकास में निरंतर निवेश आवश्यक है। विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और निजी कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना होगा। साथ ही सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी होंगी जो देश में ही एआई उपकरणों और प्लेटफॉर्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करें।

एक और महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि एआई का विकास भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के अनुरूप हो। भारत भाषाई, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत विविध देश है। पश्चिमी देशों के लिए विकसित एआई मॉडल भारत की बहुभाषी आबादी या ग्रामीण समुदायों की आवश्यकताओं को पूरी तरह नहीं समझ सकते। इसलिए एआई समाधान स्थानीय जरूरतों के अनुरूप और समावेशी होने चाहिए। भाषा मॉडल, डिजिटल सहायक, स्वास्थ्य संबंधी तकनीक और कृषि आधारित समाधान ऐसे डेटा पर आधारित होने चाहिए जो भारत की विविध जनसंख्या को प्रतिबिंबित करते हों। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो एआई असमानताओं को कम करने के बजाय उन्हें और गहरा कर सकता है।

एआई के संदर्भ में नैतिक प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। डेटा की गोपनीयता, एल्गोरिदमिक पक्षपात, निगरानी और भ्रामक सूचनाओं का प्रसार जैसी समस्याएँ तेजी से उभर रही हैं। भारत जैसे विशाल और लोकतांत्रिक देश में एआई का दुरुपयोग दूरगामी परिणाम ला सकता है। डीपफेक, स्वचालित प्रचार और पक्षपाती निर्णय प्रणाली लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुँचा सकती हैं। इसलिए आवश्यक है कि ऐसे ठोस नियम बनाए जाएँ जो नवाचार को प्रोत्साहित करें, लेकिन जवाबदेही और पारदर्शिता भी सुनिश्चित करें। डेटा संरक्षण, एल्गोरिदम की स्पष्टता और शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था किसी भी व्यापक एआई नीति का हिस्सा होनी चाहिए।

रोजगार पर एआई का प्रभाव भी एक जटिल चुनौती है। एआई आधारित स्वचालन पारंपरिक नौकरियों को प्रभावित कर सकता है, चाहे वे विनिर्माण क्षेत्र की हों या सेवा क्षेत्र की। यहाँ तक कि कई श्वेत कॉलर पेशे भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। यद्यपि एआई नए रोजगार अवसर भी उत्पन्न करेगा, जैसे डेटा विज्ञान, रोबोटिक्स और डिजिटल सेवाओं में, परंतु इस परिवर्तन का प्रभाव सभी वर्गों पर समान रूप से सकारात्मक नहीं होगा। जिन लोगों के पास डिजिटल कौशल नहीं हैं, उन्हें रोजगार संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस जोखिम को कम करने के लिए व्यापक स्तर पर कौशल विकास और पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने होंगे। शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को अपने पाठ्यक्रम में एआई साक्षरता, कोडिंग, डेटा विश्लेषण और आलोचनात्मक चिंतन जैसे विषयों को शामिल करना होगा। जीवन भर सीखने की संस्कृति को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना समय की मांग है।

शिक्षा प्रणाली को भी एआई युग के अनुरूप बदलना होगा। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में एआई को केवल तकनीकी विषय के रूप में नहीं, बल्कि एक बहु-विषयक अध्ययन के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें नैतिकता, कानून, समाजशास्त्र और लोक नीति जैसे आयाम भी हों। विद्यार्थियों को एआई की क्षमताओं के साथ-साथ उसकी सीमाओं की भी समझ होनी चाहिए। आरंभिक स्तर से ही शोध और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना आवश्यक है, ताकि भविष्य की पीढ़ी जिम्मेदारी के साथ एआई का उपयोग कर सके। जन-जागरूकता अभियान भी लोगों को एआई के बारे में सही जानकारी देने और उसे समझदारी से अपनाने में सहायक हो सकते हैं।

स्वास्थ्य, कृषि, शासन और जलवायु प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग से भारत को व्यापक लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं में एआई प्रारंभिक निदान, व्यक्तिगत उपचार और अस्पताल प्रबंधन में सहायता कर सकता है। कृषि में यह मौसम पूर्वानुमान, फसल प्रबंधन और जोखिम कम करने में मददगार हो सकता है। शासन में डेटा आधारित विश्लेषण से नीतियों की गुणवत्ता और सेवा वितरण की दक्षता बढ़ाई जा सकती है। किंतु इन क्षेत्रों में एआई का उपयोग सावधानीपूर्वक होना चाहिए। पूरी तरह स्वचालित प्रणालियों पर निर्भरता से बचते हुए मानवीय निगरानी और नैतिक सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एआई के दौर में साइबर सुरक्षा भी एक गंभीर चिंता का विषय है। जैसे-जैसे एआई प्रणालियाँ उन्नत होती जा रही हैं, वैसे-वैसे साइबर हमलों के तरीके भी जटिल होते जा रहे हैं। दुर्भावनापूर्ण तत्व एआई का उपयोग करके डिजिटल ढांचे को नुकसान पहुँचा सकते हैं या गलत सूचनाएँ फैला सकते हैं। इसलिए मजबूत साइबर सुरक्षा तंत्र, सुरक्षित एआई संरचनाएँ और अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक हैं।

एआई क्रांति भारत के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। देश को ऐसा संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा जो नवाचार को बढ़ावा दे, लेकिन सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी सुनिश्चित करे। स्वदेशी तकनीकी विकास, नैतिक शासन, समावेशी नीतियाँ और मानव संसाधन में निवेश यह तय करेंगे कि भारत वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ेगा या बाहरी तकनीकों पर निर्भर रह जाएगा। एआई की सच्ची सफलता तभी होगी जब इसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा मानवीय गरिमा की रक्षा हो सके।

अनुशासन , निरंतर एकाग्रता से तैयारी और आत्मविश्वास को मूल मंत्र बनाकर सिविल जज बने अभिनव अग्रवाल

छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा आयोजित व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा 2024 में अभिनव रहे 19वीं रैंक पर

Mantra of success

राजेश शर्मा

वरिष्ठ पत्रकार एवं मोटिवेशनल स्पीकर

'आये हो निभाने को जब, किरदार जमीं पर
कुछ ऐसा कर चलों कि जमाना मिसाल दे'

आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से ओतप्रोत इस संभावनावान, प्रतिभाशाली युवा ने अपनी प्रतिभा और संभावनाओं के दर्शन करा दिए थे कि एक दिन यह प्रतिभा अपनी उजास की चमक बिखेरेंगी ... छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा आयोजित व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा 2024 में सिविल जज बन कर दर्शा दिया कि

'गर स्वप्न आसमां की तरह बड़े हो , तो उड़ान भी उतनी ही ऊंची होगी'।

धारा नगरी जैसे 'छोटे से स्थान से निकली इस बड़ी प्रतिभा' ने यह जता दिया कि जो भी लक्ष्य निर्धारित करे उस पर अडिग रहे, स्वयं पर विश्वास बनाए रखें और परिश्रम में कोई कमी ना रखें जैसे मूल मंत्र को अपनाकर सफलता हासिल की जा सकती है।

धार की माटी में शिक्षा- दीक्षा और संस्कार ग्रहण कर छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा आयोजित व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा 2024 में 19 वी रैंक प्राप्त कर सिविल जज बन कर धार शहर ही नहीं बल्कि धार जिले को छत्तीसगढ़ में गौरवांवित किया है और यह भी दर्शा दिया कि 'छोटे शहरों से भी बड़ी प्रतिभाएं निकल रही हैं ' "Mantra Of Success" में छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा आयोजित व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा 2024 में 19 वी रैंक प्राप्त कर सिविल जज बने अभिनव अग्रवाल से राजेश शर्मा द्वारा लिए साक्षात्कार के अंश ...

अभिनव ने प्राथमिक शिक्षा श्री सी.के. चंदेल स्कूल, धार से पूरी कर स्कूल ऑफ लॉ, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से बी.ए.एल.एल.बी. (ऑनर्स) और रेनेसां यूनिवर्सिटी से एल.एल.एम. किया है।

प्रश्न- न्यायिक सेवा में जाने की प्रेरणा कब मिली ?

अभिनव अग्रवाल - दादाजी धार जिले के प्रतिष्ठित एडवोकेट रहे और पापा की ख्याति प्रसिद्ध अधिवक्ता के रूप में हैं । परिवार के माहौल से मुझे न्यायिक सेवा में जाने की प्रेरणा मिली।

मैं अपनी इस उपलब्धि को अपने परिवार को समर्पित करता हूँ। उन्होंने हर परिस्थिति में निरंतर मेरा साथ दिया और मुझे प्रेरित किया है।

प्रश्न- सफलता की राह में आई चुनौतियां और संघर्ष से कैसे निपटा , संघर्ष की कहानी ?

अभिनव अग्रवाल - जब लक्ष्य बड़ा होता हैं तो निश्चित ही संघर्ष अधिक बड़ा होता हैं। संघर्ष व चुनौतियों से विजय हासिल करने के मेरे प्रयासों में मेरे माता - पिता ही मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं।

इसके अतिरिक्त जब लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया तो संघर्ष और चुनौतियां भी हौसलों में परिवर्तित होकर उत्साह बढाने लगती हैं।

प्रश्न- यह सफलता आपको कितने प्रयासों में मिली ?

अभिनव अग्रवाल - छत्तीसगढ़ में मेरा यह प्रथम प्रयास था।

प्रश्न - सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे ?

अभिनव अग्रवाल - मेरी सफलता की इस राह में मुझसे जुड़े हर व्यक्ति ने एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया हैं।

मेरी दादी, माता - पिता , मेरी बहन एवं मेरा परिवार, मेरे मेंटर्स, मेरे मित्र सभी का मेरी सफलता में योगदान रहा हैं।मेरे पिताजी संजय अग्रवाल, धार में प्रसिद्ध वकील है। मेरी माताजी रेखा अग्रवाल गृहिणी है। बहन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मैं अपने शिक्षक श्री राजेश शर्मा सर को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके मार्गदर्शन से ही यह संभव हो सका है।

प्रश्न - सफलता का मूल मंत्र क्या है ? यूथ को क्या मोटिवेशनल टिप्स देना चाहेंगे ?

अभिनव अग्रवाल - अनुशासन बना कर निरंतर एकाग्रता से तैयारी करने और आत्मविश्वास बनाये रखने से लक्ष्य अवश्य हासिल होता है ।

पीएससी-सीएससी में प्रसव कराने के बजाए कर रहे रेफर

एस. द्विवेदी, बैतूल। जिला अस्पताल में वैसे ही चिकित्सकों की कमी बनी हुई है। ऊपर से पीएससी-सीएससी केन्द्रों से रेफर होकर आने वाले मरीजों के कारण जिला अस्पताल पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। केवल गर्भवती महिलाओं की डिलवेरी (प्रसव) की बात करे तो यहां प्रतिमाह औसतन 300 से अधिक महिलाओं की डिलेवरी कराई जा रही है। जिसमें रेफर होकर आने वाली महिलाओं की संख्या ही 40 से 50 फीसदी करीब बताई जा रही है, जबकि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पीएससी और ब्लाक स्तरों पर सीएससी केन्द्र खोले गये है, ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके बावजूद रैफर सिस्टम के कारण अधिकांश गर्भवती महिलाओं को सीधे जिला अस्पताल भेज दिया जा रहा है। परिणाम स्वरूप जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं तो बिगड़ रही है, साथ ही डॉक्टरों और स्टॉफ पर भी काम का बोझ बढ़ रहा है। वर्तमान में कार्यरत पांच पीजीएमओ महिला चिकित्सकों की राउंड द क्लॉक ड्यूटी रहती है। जिससे उन्हें लगातार कार्यभार झेलना पड़ता है। पूर्व में जिला अस्पताल से प्रसव का दबाव कम करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन पीएससी-सीएससी स्तर पर रैफर व्यवस्था में सुधार नहीं होने के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके।

काम की अधिकता और स्टॉफ की कमी से बढ़ रहा काम का दबाव – बता दे कि जिला अस्पताल में सालाना 7 हजार से अधिक महिलाओं के प्रसव होते है। मदर चाइल्ड केयर यूनिट में डिलेवरी के लिए करीब 21 स्टॉफ कार्यरत है। इसमें स्टॉफ नर्स, विशेषज्ञ लेडी डॉक्टर और पांच पीजीएमओ महिला चिकित्सक शामिल है, जबकि जानकारों के अनुसार मदर चाइल्ड केयर यूनिट के बेहतर संचालन के लिए चार अतिरिक्त लेडी मेडिकल ऑफिसर की आवश्यकता है। वर्तमान में जो पीजीएमओ महिला चिकित्सक कार्यरत है, उनकी राउंड द क्लॉक ड्यूटी रहती है। जिससे उन पर लगातार कार्यभार बढ़ता जा रहा है। जानकारों का मानना है कि यदि पीएससी और सीएससी पर गर्भवती महिलाओं की नियमित मॉनीटरिंग, समय पर जांच और नार्मल डिलेवरी की व्यवस्था को मजबूत किया जाये तो जिला अस्पताल पर बढ़ता दबाव काफी हद तक कम किया जा सकता है।

निर्देशों का असर नही, डिलेवरी केस आते ही रेफर – स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर पीएससी और सीएससी स्तर पर अनावश्यक रेफर पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। निर्देशों के अनुसार नार्मल डिलीवरी के मामलों को स्थानीय स्तर पर ही निपटाने की व्यवस्था की जानी थी। हालांकि व्यवहारिक स्तर पर इन निर्देशों का प्रभाव दिखाई नहीं देता। कई मामलों में गर्भवती महिलाओं की समुचित जांच और नियमित मॉनिटरिंग किए बिना ही उन्हें गंभीर बताकर जिला अस्पताल रैफर कर दिया जाता है। जिसके कारण मरीज और उनके परिजन तो परेशान होते ही है, साथ ही जिला अस्पताल पर भी अनावश्यक कार्य का दबाव बना रहता है। कई बार तो ऐसे भी प्रसव केस देखे गये, जिन्हें पीएससी-सीएससी में गंभीर बताकर रेफर किया जाता है, लेकिन जिला अस्पताल में पहुंचने वाली अधिकांश महिलाओं की नार्मल डिलेवरी हो जाती है।

9 महीने में 5120 डिलवेरी, 2115 रैफर होकर आई – जिला अस्पताल में पहुंचने वाली अधिकांश महिलाओं की नार्मल डिलवेरी हो जाती है। जिला अस्पताल के आंकड़ों पर नजर डाली जाये तो विगत 9 माह यानि अप्रैल से दिसंबर 2025 तक जिला अस्पताल में कुल 5120 महिलाओं की डिलवेरी कराई गई। इनमें 3768 महिलाओं की नार्मल डिलवेरी हुई, जबकि 1352 मामलों में सिजेरियन करना पड़ा। आंकड़े यह भी दर्शाते है कि प्रसवों में नार्मल डिलवेरी का प्रतिशत कहीं अधिक है। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में 5120 महिलाओं की डिलवेरी कराई गई है, उसमें से 2115 महिलाएं रैफर होकर आई थी, जिन्हें पीएससी और सीएससी से गंभीर स्थिति बताकर रैफर किया गया था। जिसके बाद इनकी डिलवेरी भी जिला अस्पताल में कराई गई।

इनका कहना है –

यह सहीं है कि जिला अस्पताल में रेफर केसों की संख्या काफी बढ़ रही है। कुछ मामलों में तो क्रिटिकल कंडीशन बताकर गर्भवती महिलाओं को जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। लेकिन यहां आकर नार्मल डिलेवरी हो जाती है। रैफर होकर आने वाले मरीजों की वजह जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर असर पड़ता है।

– डॉ. जगदीश घोरे,
सिविल सर्जन, जिला अस्पताल बैतूल

प्रकृति वात्सल्य गौशाला की जमीन पर उद्योग बसाने का आरोप, मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग

गौशाला समिति, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने उद्योग विभाग पर गौशाला की भूमि पर अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

धार । जिले के ग्राम जेतपुरा स्थित प्रकृति वात्सल्य गौशाला समिति एवं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने उद्योग विभाग पर गौशाला की भूमि पर अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। गौ सेवकों और नागरिकों में प्रशासन की इस कार्रवाई से खासा आक्रोश देखा गया।

समिति के अनुसार खसरा क्रमांक 756 में संचालित गौशाला में लगभग 300 बीमार, दुर्घटनाग्रस्त एवं निराश्रित गौवंश का संरक्षण किया जा रहा है।

गौशाला प्रबंधन का आरोप है कि समीपस्थ खसरा क्रमांक 755 एवं आसपास की भूमि पर विकसित किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्र के लिए गौशाला से लगी भूमि के प्लॉट काटे गए हैं तथा बिना उचित सीमांकन तार फेंसिंग कर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। नियमों के अनुसार गौशाला संचालन के लिए 12 एकड़ भूमि आरक्षित रहना आवश्यक है, जबकि वर्तमान में गोचर भूमि प्रभावित हो रही है।

समिति ने कहा कि यदि चराई भूमि समाप्त हुई तो गौवंश के आहार-पाचन पर असर पड़ेगा और मृत्यु दर बढ़ सकती है। साथ ही औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषण से भी पशुओं को नुकसान की आशंका है।

गौशाला प्रबंधन ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के भूखंड क्रमांक 100 से 112 को डीनोटिफाई किया जाए तथा गौशाला एवं गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर सुरक्षित किया जाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गौशाला के सदस्य एवं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के योगेंश पाल सिंह ने चेतावनी दी कि यदि शासन- प्रशासन इस दिशा में यदि कोई शीघ्र कार्रवाई नहीं करता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा ।

इस अवसर पर समाजसेवी समंदर पटेल, प्रकृति वात्सल्य गौशाला समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र जोशी, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी देवकरण जाट, समिति की सचिव विजया शर्मा, संस्थापक अध्यक्ष प्रमिला शर्मा, ममता जोशी, संतोष पुरोहित, प्रवीण कोठारी, राजू लब्दी सेठ ,मीना दुबे, रीमा राठौर , प्रतिभा शर्मा , बिंदिया रघुवंशी, अशोक शास्त्री, डॉ. तरुण जोशी, अभय जैन,मोतीलाल लश्करी श्रीकांत द्विवेदी, मनीष भार्गव, विजय अग्रवाल, राजेश शर्मा, दीपक शर्मा, लालू यादव, गोटू शुक्ला ,अजय ठाकुर डॉ दीपक नाहर , प्रवीण शर्मा, आनंदीलाल व्यास, अनिल तिवारी, लक्की उस्ताद, चुन्नू बाजपेई, प्रशांत रावल, जितेंद्र पंड्या, विजय दवे, देवेंद्र शर्मा, महेंद्र जोशी, नीलेश जोशी आशीष पटेल , बजरंग दल से योगेश पाल, अरविन्द वैष्णव, जगदीश काकरवाल, अनुराग भाटी, पियूष परमार आदि उपस्थित थे। ज्ञापन का वाचन योगेंश पाल सिंह ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में धार शहर के प्रतिष्ठित नागरिक, समाजसेवी, बार एसोसिएशन से अनेक अधिवक्ता, पत्रकारगण, मातृशक्ति उपस्थित थी।

समीपवर्ती नर्मदा नदी घाट पर भंडारे का आयोजन

सोहागपुर। प्राचार्य धनराज तिवारी एवं समाजसेवी संजय खंडेलवाल ने सपत्नीक मां नर्मदा की परिक्रमा 11 दिनों में पूर्ण की। इसके उपरांत विगत दिवस क्षेत्र के प्रसिद्ध रेवा बनखेड़ी के नर्मदा नदी घाट परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे के आयोजन में शंभू दरबार के पंडित प्रकाश मनमोहन मुद्गल डाक्टर सोमेश सिटोके सहित नगर के समाजसेवी, राजनैतिज्ञ गणमान्य नागरिक एवं मातृशक्ति भारी संख्या में शामिल हुए। इसके अलावा दोनों परिक्रमा वासियों के अन्य नगरों पधारे रिश्तेदार भी भारी संख्या पहुंचकर में भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर संजय खंडेलवाल ने बताया कि हमने नर्मदा परिक्रमा 11 दिनों में पूर्ण की है।यह यात्रा ओम्कारेश्वर ज्योतिर्लिंग से प्रारंभ की थी। वहीं यात्रा पुनः ओम्कारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर पूर्ण की। वहीं अपने गृह निवास के समीपवर्ती ग्राम रेवा बनखेड़ी के विख्यात नर्मदा नदी घाट पर भंडारे का आयोजन किया।

नगर विकास को लेकर बैठक संपन्न

सोहागपुर। स्थानीय काली मंदिर परिसर में संघर्ष समिति ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने शिवाजी महाराज के संघर्षों को याद किया गया। समाजसेवी कन्नूलाल अग्रवाल ने शिवाजी महाराज के सम्पूर्ण जीवन चरित्र का विस्तार से वर्णन किया । इसके बाद नगर विकास के संबंध में सभी उपस्थित जनों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए।

संघर्ष समिति के संयोजक शिवकुमार पटेल ने बताया कि रेलवे समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्रीय सांसद से आग्रह करके रेल मंत्री से समय लिया जाएगा। नगर का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली जाकर रेल मंत्री से भेंट करेगा। रेल मंत्री को सोहागपुर रेल्वे स्टेशन की समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। ताकि उनका निराकरण हो सके।इसी क्रम में नगर विकास की समस्याओं पर चर्चा की गई। जिसमें समस्त रेवा बनखेड़ी से रामगंज को जोड़ने लिपटा निर्माण ,तिलक वार्ड आदि को जोड़ने को रेल्वे ब्रिज के नीचे पलकमती नदी पर लिपटे का निर्माण,नगर समस्त विभागों का एकीकृत भवन निर्माण एवं सुलभ काम्प्लेक्स बनाने, स्कूलों के सामने स्पीड ब्रेकर एवं डबल लाक केन्द्र खोलने के साथ नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए ठहरने की व्यवस्था करने का संकल्प लिया गया। इस बैठक में नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

ग्रीष्म ऋतु के लिए कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने प्रभावी पेयजल कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देश

संकल्प से समाधान अभियान के आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण हो

बैतूल। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने समय-सीमा बैठक में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लक्ष्य अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की समीक्षा कर निर्धारित लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रगति लाने के लिए श्रम पदाधिकारी एवं सभी जनपद सीईओ को निर्देश दिए। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत बैंक स्तर पर लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने को कहा। राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने राजस्व, खनिज, परिवहन और पंजीयन विभागों को निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की नल-जल योजनाओं की समीक्षा में उन्होंने निर्देशित किया कि सभी एकल ग्राम नल-जल योजनाओं को शीघ्र हर घर जल घोषित करने की कार्रवाई पूर्ण की जाए। उन्होंने जनपद सीईओ एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए ग्रामवार पेयजल प्रबंधन की प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संकल्प से समाधान अभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि शिविरों में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए ताकि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। बैठक में फायर स्टेशन हेतु भूमि आवंटन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की तिथियों का निर्धारण, किसानों के फॉर्मर आईडी का शत-प्रतिशत निर्माण, आधार नामांकन, फसल सांख्यिकीय संकलन सहित अन्य समसामयिक विषयों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि योजनाओं के लक्ष्यों को समय पर पूरा करें तथा प्राप्त वित्तीय आवंटन का सदुपयोग सुनिश्चित करें। लापरवाही से आवंटन लैप्स होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम पर प्रशिक्षण आयोजित

बैतूल। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत एएनएमटीसी प्रशिक्षण केन्द्र टिकारी बैतूल में 23 फरवरी को चिचोली, घोडाडोंगरी आमला, शाहपुर मुलताई एवं प्रभात पट्टन के कम्युनिटी हेल्थ ऑफीसर को प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज कुमार हुरमाडे ने बताया ने कि प्रत्येक ऋतु अनुसार अलग-अलग मौसमी परिवर्तन देखने को मिलते है,जिससे मानव स्वास्थ प्रभावित होता है, कैसे हमारे छोटे छोटे प्रयासों से हम प्रकृति को होने वाले नुकसानों से बचा सकते है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन से होने वाले स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देकर बताया कि कैसे हम हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाकर अपने स्वास्थ में हो रहे बदलावों को नियंत्रित कर सकते है। प्रशिक्षण में जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी डॉ राजेश परिहार द्वारा मौसम परिवर्तन का प्रभाव और बचाव की जानकारी दी। इस विषय पर सभी प्रतिभागियों द्वारा पोस्टर प्रेजेंटेशन का भी आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से प्रतिभागियों ने अपने-अपने अनुभव साझा किए। भवनेश देशमुख जिला डाटा मैनेजर के द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की विस्तृत जानकारी को प्रस्तुत किया गया।

शहर में बिगड़ती पेयजल व्यवस्था को लेकर पार्षद ने दिया ज्ञापन, चिकना नाला के विस्तार की मांग

आधे से ज्यादा शहर की पेयजल आपूर्ति कर सकता है चिकना नाला

आमला। शहर के सबसे पुराने और भरोसेमंद एकमात्र जल स्त्रोत चिकना नाला के विस्तारीकरण को लेकर वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद राकेश शर्मा ने नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन दिया है, पार्षद शर्मा ने नगर पालिका अधिकारी को दिए अपने ज्ञापन में कहा है कि स्थानीय शासन प्रशासन ने बीते कई वर्षों में शहर की पेयजल व्यवस्था के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं,किंतु फिर भी शहर में पेयजल व्यवस्था को लेकर हालत ज्यादा बदल नहीं पाए हैं।

अब ग्रीष्म ऋतु शुरू हो चुकी है ऐसे में हर साल की तरह इस साल फिर जल संकट के आसार नजर आने लगे है,ऐसे में पार्षद शर्मा ने नगर पालिका के तमाम जल स्त्रोतों के अलावा अपने परंपरागत और दशकों पुराने जल स्त्रोत चिकना नाला को गर्मियों के विपरीत हालातो में एक मजबूत विकल्प बताया है। ज्ञापन में कहा गया है कि चिकना नाला पर नगर पालिका का पूरा सिस्टम पहले से ही लगा हुआ है,लेकिन नगर पालिका ने चिकना नाला को बदहाल हालत में पहुंचा दिया है, इस ओर शीघ्र ध्यान देने की मांग की गई है। इस मौके पर पार्षद ने पूरी परिषद को चिकना नाला के निरीक्षण और त्वरित निर्णय की मांग भी नगर पालिका अधिकारी से की है।

आधे शहर की आपूर्ति कर सकता है चिकना नाला– जैसा कि शहर के कई जानकारों ने हमें बताया है की पंचवटी हनुमान मंदिर के पास स्थित चिकना नाला आधे से ज्यादा शहर की प्यास बुझा सकता है, किंतु नगर पालिका द्वारा साजिशन चिकना नाला को अलग-थलग किया गया है,जैसा कि इस बारे में हमें गजानंद टिकारे,भगवान दास, संजय साहू, राजकुमार सोनी आदि कई लोगों ने बताया है, कि अगर नगर पालिका चिकना नाला को लेकर गंभीरता से काम करें तो, शहर में हर साल गर्मियों में पैदा होने वाले जल संकट को काफी हद तक टाला जा सकता है।

होली से 2 दिन के अंतराल में होगी जलापूर्ति– इधर नगर पालिका द्वारा अगले माह 3 मार्च होली से पूरे शहर में दो दिन के अंतराल से पेयजल आपूर्ति की जाएगी, इस विषय में जल शाखा के प्रभारी अरुण पवार ने बताया है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए होली से 2 दिन के अंतराल से पेयजल आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है।

600 से ज्यादा नल कनेक्शन भी कटेंगे– जैसा कि नगर पालिका द्वारा बताया गया है कि पूरे शहर में लगभग 6600 नल जल उपभोक्ता है,बीते लगभग तीन वर्ष पहले पूरे शहर में सभी घरों में नल कनेक्शन दिए गए थे, किंतु जैसा कि नगर पालिका द्वारा बताया गया है कि इसमें से लगभग 600 से ज्यादा उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक नल कनेक्शन की राशि नगर पालिका में जमा नहीं की है। ऐसे में नगर पालिका ऐसे नल कनेक्शन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने का अभियान भी चला रही है।

जिल्दसाज

जिल्दसाज अब भी किताबों की जिल्द बाँधा करता था और अब भी उसके पास ग्राहक आते थे, किन्तु अब न तो वह उतनी सुन्दर जिल्दें बाँधता था और न उसके पास पहले-जैसे ग्राहक आते थे।

कहानी

वनमाली

वह अधेड़ जिल्दसाज सबेरे से शाम तक और अँधेरा होने पर दीये की रोशनी में बड़ी रात तक, अपनी छोटी-सी दुकान में अकेला एक फुट लम्बी चटाई पर बैठा किताबों की जिल्दें बाँधा करता। उसकी मोटी व भद्दी अंगुलियाँ बड़ी उतावली से अनवरत रंग-बिरंगे कागजों के पन्नों में उलझती रहतीं और उसकी धुँधली आँखें नीचे को झुकी काम में व्यस्त रहतीं।

जिल्दसाज का स्वभाव रूखा था व स्वर तीखा। ग्राहकों को अपनी मजूरी के जो दाम वह एक बार बता देता, उनमें कमी-बेशी न करने की उसे एक जिद-सी थी। लेकिन ग्राहक उसकी इस जिद और रुखाई पर भी उसके यहाँ किताबें डाल जाते, क्योंकि जिल्दसाज वास्तव में किताबों की जिल्द बहुत सुन्दर बाँधता था। किताबों की जिल्द बाँधना ही उसके एकाकी विरक्त जीवन में सत्य था और सत्य ही तो सुन्दर होता है।

एक दिन सबेरे जिल्दसाज नित्य की भाँति अपनी दुकान में बैठा काम कर रहा था कि इतने में एक स्त्री उसके सामने आ खड़ी हुई। उसके साथ उसका आठ साल का बालक भी था।

स्त्री ने पूछा ''क्यों जिल्दसाज, रहीम की किताब की जिल्द तुम्हीं ने बाँधी है?'' जिल्दसाज ने नजर ऊपर की।

रहीम? रहीम कौन? वह किसी रहीम को नहीं जानता। न जानने की उसे जरूरत ही है। यह कैसी पागल स्त्री है। काम की बात क्यों नहीं करती? उसके पास तो काम है। काम को लेकर ही वह जीता है। काम ही उसे सही रास्ते पर ले जा रहा है। उसके पास ऐसी कहाँ फुरसत, जो वह किसी से अपना सरोकार जोड़े। जिल्दसाज बोला ''मुझे नहीं मालूम। तुम अपना काम बताओ।''

स्त्री जिल्दसाज के रूखे जवाब से झेंप गई। उसने बताया ''भाई, रहीम की किताब की जिल्द देखकर मेरा लड़का भी अपनी फटी की जिल्द बँधाने के लिये जिद पकड़े हुए है। यह रही किताब। बताओ, क्या लोगे?''

जिल्दसाज ने स्त्री के हाथ से किताब लेकर उसे उल्टा-पल्टा। तब लापरवाही से उसने यह कह दिया ''छै आने पैसे होंगे।''

जिल्दसाज के लिये सौदा तय रहा, इससे वह काम में लग गया।

पर स्त्री के पास तो पैसों का सवाल था।

वह बोली ''भाई, छै आने तो बहुत होते हैं। मैं मेहनत-मजूरी करके पेट पालने वाली कहाँ से पाऊंगी? मुझसे तीन आने ले लेना। मैं तुम्हारा बड़ा गुन मानूँगी।''

जिल्दसाज भुनभुना उठा।

उसकी बात को दुलखने वाली यह स्त्री कौन होती है? उसकी बात आज तक किसी ने नहीं दुलखी। हमेशा उसे मुँह माँगे दाम मिले हैं। उसने जो चाहा है, वह ग्राहकों ने खुशी से दिया है और क्यों न देंगे? वह क्या कोई काम में खोट करता है? तब इस स्त्री का उसकी हेठी करने का क्या मतलब? काम की बात में गुन-एहसान की क्या बात? उसका सम्बन्ध तो इस दुनिया से अब तक लेन-देन रहा है। वह तो केवल अपनी मजूरी और चोखे काम को चीन्हता है। उसे दया और एहसान की बात क्या मालूम?

जिल्दसाज ने बताया ''छै आने से मैं एक कौड़ी भी कम नहीं लूँगा।''

स्त्री ने आजिजी की ''भाई, खुदा तुम्हें बहुत देगा। तुम्हारी मेहरबानी से मेरे बच्चे का दिल रह जायेगा।''

जिल्दसाज इस बार चिढ़ गया।

खुदा? खुदा को वह क्या जानता है? कुल जमा उसने अपनी दुकान से ही जीने के लिए पूँजी पायी है। रोजगार, किताबें, कागज बस इन्हीं के बीच तो उसकी जिन्दगी के लम्बे-लम्बे बरस कटे हैं। उसने तो कभी नहीं महसूस किया कि इस जिन्दगी को चलाने के लिए खुदा की भी कहीं किसी तरह से जरूरत पड़ती है। तब खुदा क्या खाक मदद करेगा?

जिल्दसाज झल्लाकर बोला ''मैं खुदा-उदा की बात नहीं जानता। जब तेरे पास पैसे ही नहीं थे, तब तू यहाँ क्यों आयी? जा, सिर न खा। काम करने दे।''

जिल्दसाज फिर किसी किताब के पन्ने ठीक जमाने लगा।

लेकिन इस तरह से डाँटे जाने पर भी स्त्री वहाँ से नहीं टली और उसका बालक भी उसी तरह घबराहट से अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ा रहा। स्त्री कभी काम करते जिल्दसाज को देखती और कभी उसकी निगाह जिल्दसाज की जालों और गर्द से भरी दुकान की दीवारों से टकराती। एकाएक कोई बात उसे सूझ गई।

स्त्री ने सहमते-सहमते पूछा ''अच्छा, भाई बाकी बचे तीन आने में मैं तुम्हारी दुकान झाड़-बुहार दूँ और जाले व गर्द साफ कर दूँगी। तब तो तुम मेरे बच्चे की किताब की जिल्द बाँध दोगे?''

जिल्दसाज अब सचमुच असमंजस में पड़ गया। ऐसा गरीब ग्राहक उसकी जिन्दगी में अब तक नहीं गुजरा था। उसने काम छोड़ स्त्री पर निगाह डाली। अचानक उसकी दिल की बस्ती में नमी छा गई। उसने पहली बार स्त्री के दीन और निस्सहाय चेहरे को देखा। उसकी पैबन्दों से भरी ओढ़नी को परखा। लड़के का मासूम और बेबस चेहरा भी उससे छिपा नहीं रहा। जिल्दसाज के अन्तस में आज पहली बार रहम बरस पड़ा।

जिल्दबाज तब अपने को छिपाते हुए बोला- ''अच्छा दो किताब। मैं मुफ्त बाँध दूँगा। कल आकर तुम ले जाना।''

जिल्दसाज फिर किताब ले, बिना उस स्त्री और बालक की ओर देखे, झट कागजों की कतरन में कोई चीज खोजते खो गया।

दूसरे दिन वह स्त्री अपने बालक के साथ किताब लेने आई। जिल्दसाज ने किताब निकाल बालक को दे दी।

बालक किताब देख खुशी से नाच उठा।

बोला- ''इतनी सुन्दर जिल्द तो माँ, रहीम की किताब की भी नहीं बँधी।''

माँ अपने बच्चे की खुशी में फूल उठी। वह जिल्दसाज से बोली ''भाई खुदा तुम्हारी रोजी में बरकत दे।''

किन्तु जिल्दसाज यह सब कुछ नहीं देख-सुन रहा था। वह इस ध्यान में उलझा था कि इन दो परदेशियों से किसी अनजाने क्षण में उसकी जो पहचान जुड़ गई है, वह क्या यहीं टूटकर खत्म हो जायेगी? वह अब अपने अकेलेपन से ऊब उठा था। उसके लिए अब जगत का कोई अर्थ हो आया था। उसका मन अब रोजी को ही सब कुछ मानने से इन्कार करने लगा। उसके अन्दर एक निराली प्यास उठ आयी थी। उसे मालूम पड़ रहा था कि वह प्यास किसी से अपना सरोकार जोड़कर ही शान्त की जा सकती है।

जब स्त्री बन्दगी करके चलने लगी, तब जिल्दसाज जैसा रूखा आदमी भी विकल हो उठा। उसने रुकते-रुकते कहा- ''तुम कहाँ रहती हो?''

स्त्री का जवाब हुआ ''इसी मुहल्ले में रहती हूं। आपकी दुकान से पन्द्रह-बीस घर छोड़ कर के।''

''तुम्हारे खाविन्द क्या करते हैं?'' जिल्दसाज ये पूछते हुए इधर-उधर झाँक रहा था।

स्त्राी ने बताया ''मेरे खाविन्द का इन्तकाल हुए तो चार बरस होने आये।''

''तो तुम गुजर कैसे करती हो?'' जिल्दसाज का यह तीसरा प्रश्न था।

स्त्राी बोली ''मैं बेलें बनाती हूँ, बूटे काढ़ती हूँ और जरी का काम भी कर लेती हूँ। मगर आजकल यह मजूरी भी मुश्किल हो गयी है।'' जिल्दसाज न जाने कुछ देर तक क्या सोचता रहा। तब उसने कहा- ''तो सुनो। अगर तुम्हें उज्र न हो तो बगल वाला मेरा जो कमरा खाली है, उसमें तुम आकर रह सकती हो। मेरे लिए तुम रसोई बनाना। मैं ऊपर से तुम्हें चार रुपया महीना दूँगा।''

स्त्री एक बारगी इतनी ढेर-सी मेहरबानी न सह सकी। उसका सिर कृतज्ञता से भार से झुक गया। वह धीमे स्वर में बोली ''शुक्रिया करती हूँ। आपने मुझ गरीब औरत को उबार लिया।''

आज जब स्त्री और उसका बालक खुश होते हुए घर चले गये, तब जिल्दसाज सूना-सा, खोया-सा, लोगों की आती-जाती भीड़ को देखता अपनी उसी एक फुट चटाई पर सिकुड़ा अकेला बैठा था।

अगले दिन वह स्त्री अपने कपड़े-लत्तों का एक टीन का बक्स, एक बिस्तर तथा दो-चार एल्यूमीनियम के बरतन ले जिल्दसाज के यहाँ चली आयी।

जिल्दसाज की जिन्दगी में एक नया जमाना आया। उसका बर्ताव अब अपने ग्राहकों से रूखा नहीं होता था। वह बड़ी मुलायमी से उनसे पेश आता। दामों के लिए भी वह अब पहले के समान जिद नहीं करता। उनमें कमी-बेशी करके भी वह लोगों की किताबें डाल लेता।

जिल्दसाज जब किताबों की जिल्द बाँधने बैठता, तब वह पहले-जैसा एकाग्र चित्त नहीं रहता। बीच-बीच में वह बच्चे का पाठ सुनता और कभी उसके मांग करने पर उसे रंगीन कागजों की नावें व दवातें बनाकर देता। जिस दिन खेल-तमाशा होता, उस दिन वह बालक को अपने साथ लिवा ले जाकर तरह-तरह के खिलौने व मिठाइयाँ दिला लाता।

शाम को जब वह काम से ऊब जाता, तब दुकान बंद कर देता। मुँह-हाथ धोकर नमाज पढ़ता व झुटपुटे में दुकान के चबूतरे पर बैठा आते-जाते लोगों को देखा करता और न जाने क्या सोचा करता!

रात होने पर वह बड़ी चाह से घर के भीतर रोटी खाने जाता। उसके साथ उस स्त्री का बालक रज्जब भी खाने बैठता। खाते-खाते जिल्दसाज भोजन की आलोचना करता और स्त्री शर्माती-सी उसकी बातों का जवाब देती। उस समय जिल्दसाज के नीरस-विरक्त जीवन में रस ही रस छलका दीख पड़ता।

एक दिन जिल्दसाज ने खाते-खाते रज्जब की माँ से पूछा ''क्यों जी, तुम्हारा नाम क्या है? यह तो तुमने कभी नहीं बताया।''

स्त्री भेदभरी हँसी हँसकर कहा ''नाम जानकर क्या करिएगा?''

जिल्दसाज जैसे पकड़ा गया। वह बोला ''नाम का क्या किया जाता है? मैं उसी नाम से पुकारूँगा। और क्या?'' स्त्री ने तब चूल्हे की आग तेज करते हुए बताया ''गुलशन।''

''अच्छा, तो मैं तुम्हें अब 'गुल' कहकर पुकारूँगा।'' जिल्दसाज ने बड़ी संजीदगी से कहा।

गुलशन के गोरे गाल लाल हो गये। सुन्दर बाँकी आँखों में चिन्ता छा गयी। उसने बड़ी धीमी महीन आवाज में कहा ''नहीं-नहीं। इस नाम से मेरे खाविन्द मुझे पुकारा करते थे।''

जिलदसाज के मुँह से निकला ''तो?''

स्त्री कभी ऐसे आमने-सामने नहीं हुई थी। बोली- ''तो क्या?'' जिल्दसाज ने इस बार गुलशन की आँखों में आँखें डालकर ''तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें उस नाम से न पुकारूँ? यह नहीं होने का। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, पागलपन नहीं। बोला, मंजूर है?''

रज्जब की माँ के लिये यह एक समस्या हो गयी। अभी तक, आज तक उसने एक सेविका की भाँति जिल्दसाज को प्रसन्न रखने की कोशिश की थी। उसकी हँसी का अपनी हँसी से उत्तर दिया था।

गुलशन ने सफाई दी ''मुझे माफी दो। मुझे इन काँटों में न घसीटो। मुझ बेकस को यों ही पड़ी रहने दो।''

जिल्दसाज का जोश गुलशन के जवाब से एकाएक ठंडा पड़ गया, लेकिन तब भी उसके भीतर के स्वर को ठेलते हुए जैसे उसने पूछा- ''तो क्या तुम मुझे बिल्कुल नहीं चाहतीं?''

''नहीं, सो बात नहीं। मैं तुम्हारी दिलोजान से सेवा करूँगी। तुम्हारी हँसी का जवाब हँसी से दूँगी। मगर तुमसे अर्ज है, तुम मुझसे मेरे खाविन्द की याद न छीनो।'' गुलशन की सुन्दर आँखों में करुणा बरस रही थी।

जिल्दसाज एकदम टूट गया, लेकिन बुझते दीपक के क्षणिक आलोक जैसे उत्तेजित स्वर में वह बोला ''अभी तक मैंने इस दुनिया से कुछ नहीं पाया। आज आखिरी मर्तबा तुम्हें प्यार किया है, सो तुम भी मुझे ठुकराकर चूर-चूर कर देना चाहती हो। बोलो, क्या मैं तुम्हारी थोड़ी-सी दया का भी अधिकारी नहीं?''

गुलशन बस इतना ही कह सकी ''मुझे माफी दो दो।''

जिल्दसाज निरुत्तर हो गया।

मिलन के आरम्भ में जिल्दसाज कठोर था और मिलन के अन्त में रज्जब की माँ।

जिल्दसाज अब भी किताबों की जिल्द बाँधा करता था और अब भी उसके पास ग्राहक आते थे, किन्तु अब न तो वह उतनी सुन्दर जिल्दें बाँधता था और न उसके पास पहले-जैसे ग्राहक आते थे।

विश्वमित्र 1934

आसमान से टपके, पीएमओ में अटके

मोहन का मंत्रालय

आशीष चौधरी

राज्य शासन के एक 'पुलक रहे' प्रमुख सचिव साहब की मुराद आखिरकार पूरी हो गई। भारी-भरकम विभाग और उस पर 'माननीय' की मैराथन बैठकों ने साहब का माइग्रेन बढ़ा दिया था। माननीय जब भी भोपाल पधारते, समीक्षा के नाम पर पूरा दिन ही पी जाते थे। साहब ने अपना दुखड़ा बिरादरी में क्या रोया, सरकार ने सुनी और तबादले का 'मरहम' लगा दिया। पुराने विभाग की फाइलों और बैठकों से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन नए विभाग ने 'हवा' निकाल दी है। नया विभाग भी कम वजनी नहीं है, ऊपर से मुसीबत यह कि इसके एक बड़े प्रोजेक्ट की कुंडली सीधे पीएमओ खंगाल रहा है। यानी साहब, 'बैठकों वाले माननीय' से बचकर अब सीधे 'दिल्ली की रडार' पर आ गए हैं। अब इसे राहत कहें या 'कड़ाही से निकलकर चूल्हे में गिरना', यह तो साहब की अगली छुट्टियां ही बताएंगी।

बीपी, परिसीमन और विधायक जी का 'कोना'

मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि अगले चुनाव परिसीमन और महिला आरक्षण के साये में होंगे, कई सूरमाओं की धड़कन ऊपर-नीचे होने लगा है। सत्ताधारी दल के एक 'बड़बोले' और मुखर विधायक जी पर इसका असर कुछ ज्यादा ही गहरा है। सुना है विधायक जी ने अब पूरे शहर के चक्कर छोड़कर अपनी विधानसभा के एक 'खास इलाके' में तंबू गाड़ दिया है। क्षेत्र इतना बड़ा है कि पैर थक जाएं, लेकिन अब विधायक जी को केवल उसी हिस्से से प्रेम उमड़ रहा है जो उन्हें भविष्य में सुरक्षित लग रहा है। विधायक जी के करीबी धीरे से कह रहे हैं– 'महाराज, पूरे समंदर में डूबने से अच्छा है कि इसी टापू पर कब्जा जमा लिया जाए।' यानी अब जनता से ज्यादा 'रेखागणित(ज्यामिति)' पर फोकस है।

बुखार, बजट और 'बेमिसाल' देवड़ा

विधानसभा का बजट सत्र गर्म है और विपक्ष का पारा भी, लेकिन उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने साबित कर दिया कि 'इच्छाशक्ति' के आगे थर्मामीटर की रीडिंग कोई मायने नहीं रखती। साहब को तेज बुखार था, गला इतना खराब कि शब्द भी संघर्ष कर रहे थे, लेकिन सदन में डटे रहे। विपक्ष ने आरोपों के तीर छोड़े तो देवड़ा जी ने ऐसी तुलनात्मक 'सर्जरी' की कि विरोधियों को भी लोहा मानना पड़ा। उनकी इस 'बीमार' मगर 'धारदार' परफॉरमेंस की तारीफ खुद दिग्गज कैलाश विजयवर्गीय ने भी कर दी। इसे कहते हैं– 'गला बैठा है तो क्या हुआ, विपक्ष को तो चुप बैठा दिया!' अब सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि अगर बिना बुखार के जवाब देते, तो शायद विपक्ष को सदन के बाहर ही शरण लेनी पड़ती।

निगम-मंडलों की 'वेटिंग लिस्ट' और बेचैन दिल

संगठन में तो नियुक्तियां हो गईं, लेकिन 'लाल बत्ती' के तलबगार नेताओं की निगाहें अब भी सूने पड़े निगम-मंडलों पर टिकी हैं। दो दर्जन से ज्यादा कुर्सियां धूल खा रही हैं और सरकार है कि 'शुभ मुहूर्त' निकाल ही नहीं पा रही। अब सुगबुगाहट है कि विधानसभा सत्र की थकान उतरते ही नियुक्तियों की 'लॉटरी' खुल सकती है। जो नेता अब तक दिल्ली और भोपाल की परिक्रमा कर रहे थे, वे अब फिर से एक्टिव हो गए हैं। सबको डर है कि कहीं 'आचार संहिता' या 'परिसीमन' के चक्कर में यह रेवड़ियां हाथ से न फिसल जाएं। उम्मीद और बेचैनी के बीच फिलहाल तो यही नारा चल रहा है– 'इंतजार की घड़ियां लंबी हैं, पर कुर्सी बड़ी चंगी है!'

ब्यूटीशियन से नशा देकर रेप, धर्म बदलने का दबाव बनाया

छत्तीसगढ़ की युवती ने भोपाल में 4 पर कराई एफआईआर, बोली– छोटे कपड़े पहनाकर पब ले जाते थे

भोपाल (नप्र)। छत्तीसगढ़ की 21 वर्षीय ब्यूटीशियन ने भोपाल में 3 लोगों के खिलाफ रेप और एक महिला पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने की एफआईआर कराई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अमरीन, उसकी छोटी बहन आफरीन और उसके दोस्त चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया है।

चंदन यादव
आरोपी
अमरीन उर्फ माहिरा
आरोपी
आफरीन
आरोपी

पीड़िता रविवार रात अपने मामा के साथ बागसेवनिया थाने पहुंची थी। ब्यूटीशियन ने पुलिस को बताया कि 31 दिसंबर 2024 को शाहपुरा स्थित एक होटल में दोस्त की बर्थडे पार्टी में उसकी मुलाकात एक युवती से हुई। बाद में दोनों साथ रहने लगीं। जनवरी 2025 में वे बागसेवनिया में रहने वाली अमरीन उर्फ माहिरा के पास शिफ्ट हो गईं। कुछ समय बाद पीड़िता को पता चला कि उसकी सहेली ने अमरीन के कहने पर धर्म परिवर्तन कर उसके भाई से शादी कर ली है। ड्रग्स की लत लगाने के आरोप भी पीड़िता ने लगाए हैं।

अलग-अलग समय पर कई बार रेप– पीड़िता का आरोप है कि अगस्त 2025 में अमरीन का करीबी चंदन यादव बहन से मिलाने के बहाने ले गया। उसने धमका कर रेप किया। बदनाम करने की धमकी देकर चुप करा दिया। इसके बाद अलग-अलग समय पर कई बार रेप किया।

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे छोटे कपड़े पहनाकर शहर के पब-लाउंज में ले जाया जाता था। अनजान लोगों से मेल-जोल का दबाव बनाया जाता था। इसी दौरान उस पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डाला गया।

चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया– नवंबर 2025 में अमरीन उसे गांधी नगर स्थित अब्बास नगर में अपने परिजन से मिलाने ले गई। आरोप है कि वहां अमरीन के भाई बिलाल ने चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे छोटे कपड़े पहनाकर शहर के पब-लाउंज में ले जाया जाता था

अहमदाबाद में भी दुष्कर्म किया– दिसंबर 2025 में अमरीन पीड़िता को निजी काम का हवाला देकर अहमदाबाद ले गई। वहां यासिर नामक युवक से मिलवाया। पीड़िता का आरोप है कि वहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जनवरी 2026 में वह भोपाल छोड़कर छत्तीसगढ़ अपने मामा के घर चली गई।

दूसरी पीड़िता से संपर्क के बाद शिकायत– हाल ही में सोशल मीडिया पर बातचीत के दौरान एक अन्य युवती ने भी अमरीन और उसके साथियों पर इसी तरह के आरोप लगाए। इसके बाद पीड़िता भोपाल आई और बागसेवनिया थाने में शिकायत दर्ज कराई।

ऐसे गिने गए जिले के गिद्ध, संख्या 86 से बढ़कर 156 पर पहुंच गई

इंदौर। तीन दिन से चल रही गिद्धों की गणना रविवार को खत्म हो गई। पिछली बार प्रदेशभर में 12 हजार से ज्यादा गिद्ध थे, इस बार इससे ज्यादा मिले। इंदौर वन मंडल में पिछली बार 86 गिद्ध मिले, जो इस बार बढ़कर 156 हो गए। गिद्ध प्रजाति की विशेषता यह है कि जब तक उसे अच्छा तापमान नहीं मिलता, तब तक ये अपने बड़े पंख फैला नहीं सकते और न उड़ सकते हैं। इसके चलते इनकी गिनती अलसुबह की गई। इस बार इंदौर वन मंडल में वन विभाग के अधिकारियों को गिद्धों की गिनती की ट्रेनिंग इंदौर के मास्टर ट्रेनर ने दी। इसके तहत मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार फरवरी के तेज ठंड के तीन दिन 20 से 22 फरवरी चुन लिए गए।

मध्य प्रदेश में 7 प्रजातियों के गिद्ध पाए जाते हैं, जिनमें 4 प्रजातियां स्थानीय और 3 प्रजातियां प्रवासी होती हैं। ये सर्दियों के बाद वापस लौट जाती हैं। पहला चरण तब किया जाता है, जब सभी प्रजातियों के गिद्ध घोंसले बनाकर अंडे दे चुके होते हैं या नवजात बाहर आ चुके होते हैं। फरवरी तक ये बच्चे उड़ान की तैयारी में होते हैं, इसलिए शीत ऋतु का अंतिम समय गणना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है।

मास्टर ट्रेनर ने टीम को सिखाया गिद्धों की गिनती का तरीका

अलसुबह गिद्ध नहीं उड़ते – गिद्धों की गणना ठंड के दिनों में ही इसलिए होती है, क्योंकि सुबह जब तक इनके उड़ने लायक तापमान नहीं हो जाता तब तक वे अपने ठिकानों पर ही मिलते हैं। ऐसे में सुबह ही इनकी गिनती की जाती है और यही संख्या सही साबित होती है।

दरअसल, जहां गिद्धों की बसेरा ऊंची पहाड़ी, चट्टान, किले आदि वहां सुबह 6.30 बजे वन विभाग की टीमें पहुंच गई। इन्हें दो घंटों में इनकी गिनती करने को कहा गया था। इसका बड़ा कारण यह है कि गिद्धों की प्रकृति यह है कि उन्हें सुबह धूप खिलने के बाद गर्मी मिलती है तो उनमें ऊर्जा आती है।

ठिकानों पर मिलने का कारण

अगर तापमान अच्छा नहीं रहा तो वे अपने पंख आसानी से फैला नहीं पाते। सुबह का यही दो घंटे का समय होता है जब वे अपने ठिकानों पर बैठे रहते हैं। इस दौरान उनके स्थान पर उनकी गिनती की गई। हालांकि इस बार इस बार 20 फरवरी को पहले दिन कई स्थानों पर बारिश हुई जिससे देर से गिनती हुई। इंदौर वन मंडल में ट्रेंचिंग ग्राउंड, मोहाडी फॉल, चोरल आदि क्षेत्र में टीमें तीनों दिन समय पर पहुंच गई थी।

राष्ट्रीय वनमाली कथा सम्मान समारोह-2026 आज से

सुप्रतिष्ठित कथाकार, शिक्षाविद् तथा विचारक जगन्नाथ प्रसाद चौबे ‘वनमाली जी’ के रचनात्मक योगदान और स्मृति को समर्पित संस्थान ‘वनमाली सृजन पीठ’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ कवि- कथाकार संतोष चौबे ने बताया कि इस बार 8 अलग-अलग श्रेणियों में रचनाकारों को वनमाली कथा सम्मानों से अलंकृत किया जाएगा। समारोह का शुभारंभ प्रख्यात लोक गायक प्रहलाद सिंह टिपाणिया के कबीर गायन से होगा। साथ ही ‘वनमाली कथा’ पत्रिका एवं ‘वनमाली वार्ता’ का लोकार्पण होगा। इसी समारोह में कहानी मंचन और गीत संगीत भी होगा।

विश्व रंग
वनमाली सृजन पीठ
24-25 एवं 26 फरवरी 2026
स्कोप ग्लोबल स्किल्स
भोपाल एवं रबीन्द्रनाथ टैगोर
आयोजक

‘विश्व रंग’ के अंतर्गत वनमाली सृजन पीठ, रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, स्कोप ग्लोबल स्किल्स विश्वविद्यालय एवं आईसेक्ट पब्लिकेशन द्वारा 24, 25 एवं 26 फरवरी 2026 को स्कोप ग्लोबल स्किल्स विश्वविद्यालय, भोपाल और रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल के सुरम्य परिसरों में आयोजित तीन दिवसीय ‘वनमाली कथा सम्मान समारोह’ में सभी चयनित रचनाकारों को सम्मानित किया जायेगा। यह सम्मान समारोह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ उड़िया कथाकार प्रतिभा राय के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होगा। सम्मान समारोह का शुभारंभ सुप्रसिद्ध लोकगायक पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपाणिया के कबीर गायन से होगा। ‘वनमाली कथा’ पत्रिका एवं ‘वनमाली वार्ता’ का लोकार्पण होगा। कहानी मंचन तथा गीत संगीत भी होगा।

सम्मानित रचनाकार हैं

संतोष चौबे ने कहा कि ‘वनमाली कथाशीर्ष सम्मान’ से सुप्रसिद्ध रचनाकार मृदुला गर्ग को एवं ‘राष्ट्रीय वनमाली कथा सम्मान’ से वरिष्ठ कथाकार अलका सरावगी को सम्मानित किया जायेगा। दोनों ही रचनाकारों को शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र एवं एक-एक लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान कर अलंकृत किया जायेगा। उल्लेखनीय हैं कि वनमाली सृजन पीठ ने सम्मानों की श्रृंखला में इस बार से कथा अनुवाद को प्रमुखता से सम्मिलित किया है। कथा अनुवाद को वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान दिलाने हेतु पहला ‘वनमाली कथा अनुवाद सम्मान’ वरिष्ठ साहित्यकार, अनुवादक जितेन्द्र भाटिया को प्रदान किया जाएगा।‘वनमाली कथा आलोचना सम्मान’ महेश दर्पण को, ‘वनमाली कथा मध्यप्रदेश सम्मान’ वरिष्ठ कथाकार उर्मिला शिरीष (भोपाल) को, ‘वनमाली युवा कथा सम्मान’ युवा कथाकार कुणाल सिंह को, वनमाली कथेतर सम्मान’ अयोध्या के यतीन्द्र मिश्र को प्रदान किये जाएँगे। साहित्य के क्षेत्र में डिजिटल माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान के लिए पहला ‘वनमाली डिजिटल साहित्य अवदान सम्मान’ अंजुम शर्मा को प्रदान किया जायेगा। इन सभी सम्मानित रचनाकारों को शॉल-श्रीफल प्रशस्ति पत्र एवं इक्यावन-इक्यावन हजार रुपये की सम्मान राशि प्रदान कर अलंकृत किया जाएगा।

वनमाली सृजन पीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ कवि कथाकार संतोष चौबे ने कहा कि ‘विश्व रंग’ के अंतर्गत वनमाली सृजन पीठ द्वारा प्रदान किए जाने वाले ‘वनमाली कथा सम्मान’ समकालीन कथा परिदृश्य में लोकतांत्रिक एवं मानवीय मूल्यों की तलाश में जुटे कथा साहित्य की पुनःप्रतिष्ठा करने एवं उसे समुचित सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित द्विवार्षिक पुरस्कार है। अब तक वनमाली कथा सम्मान से भारत के सुप्रतिष्ठित रचनाकारों में शुमार ममता कालिया, चित्र मुद्गल, शशांक, स्वयं प्रकाश, अखिलेश, असगर वजाहत, उदय प्रकाश, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभु जोशी, प्रियंवद, गीतांजलि श्री, मनोज रूपड़ा आदि रचनाकारों को अलंकृत किया जा चुका है।

‘वनमाली कथा’ पत्रिका एवं ‘वनमाली वार्ता’ का लोकार्पण

नई सदी की नई रचनाशीलता को सम्यक एवं समुचित स्थान देने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई लोकतांत्रिक मूल्यों की समावेशी पत्रिका ‘वनमाली कथा’ ने अपने प्रवेशांक से ही साहित्य जगत में रचनात्मक उपस्थिति दर्ज कराई है। पत्रिका का फरवरी अंक भी वनमाली कथा सम्मान समारोह में लोकार्पित किया जायेगा। इस अवसर पर वनमाली सृजन पीठ के मुखपत्र ‘वनमाली वार्ता’ का लोकार्पण भी किया जाएगा।

साहित्य पर विमर्श-आयोजित होंगे विशेष सत्र

तीन दिवसीय वनमाली कथा सम्मान समारोह के अवसर पर सम्मानित रचनाकारों के ‘रचना पाठ’ के साथ-साथ ‘डिजिटल युग में शास्त्रीय संगीत-रियाज से रील तक’, ‘डिजिटल युग में साहित्य- पाठक परिवर्तन और नयी प्रासंगिकताएँ’, ‘समकालीन युवा कहानी की संवेदनाएँ और सामाजिक परिदृश्य’ जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श के विशेष सत्र आयोजित किये जाएँगे।

रचनात्मक विचार–विमर्श के शिल्पी

राष्ट्रीय वनमाली कथा सम्मान के अवसर पर आयोजित होने वाले सत्रों में प्रतिभा राय, मृदुला गर्ग, जितेंद्र भाटिया, अलका सरावगी, महेश दर्पण, उर्मिला शिरीष, मुकेश वर्मा, संतोष चौबे, लीलाधर मंडलोई, गीताश्री, यतींद्र मिश्र, कुणाल सिंह, अंजुम शर्मा, अरुणेश शुक्ल, संजय शेफ़र्ड, कैफी हाशमी आदि की रचनात्मक भागीदारी होगी। सम्मान समारोह एवं विभिन्न सत्रों का संचालन विनय उपाध्याय, संगीता पाठक, विकास अवस्थी एवं विक्रांत भट्ट द्वारा किया जाएगा। सम्मान समारोह का संयोजन वनमाली सृजन पीठ की राष्ट्रीय संयोजक ज्योति रघुवंशी द्वारा किया जाएगा।

कहानी का मंचन एवं रंग संगीत

वनमाली कथा सम्मान के अवसर पर 25 फरवरी को शाम 4:00 बजे शारदा सभागार, रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल में श्री संतोष चौबे की कहानी ‘मगर शेक्सपियर को याद रखना’ का नाट्य मंचन वरिष्ठ नाट्य निर्देशक संजय मेहता के निर्देशन में किया जायेगा। इस अवसर पर टैगोर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा रंग-संगीत की सांगीतिक प्रस्तुतियाँ दी जाएँगी।

सम्मानित रचनाकारों का परिचय

मृदुला गर्ग

जन्म-25 अक्टूबर 1938 (कलकत्ता)

प्रकाशित कृतियाँ- कहानी संग्रह- 8 कहानी संग्रहों की सम्पूर्ण कहानियाँ ‘संगति-विसंगति’ नाम से दो खण्डों में प्रकाशित। 86 कहानियाँ, ‘सम्पूर्ण कहानियाँ’ नाम से प्रकाशित। दस प्रतिनिधि कहानियाँ, यादगार कहानियाँ, प्रतिनिधि कहानियाँ तथा नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा संकलित कहानियाँ पुस्तक प्रकाशित। उपन्यास- उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित्तकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब, मिलजुल मन, वसु का कुटुम, द लास्ट ईमेल। संस्मरण, नाटक, निबन्ध, यात्रा वृतान्त, आलोचना, साक्षात्कार, व्यंग्य की कई पुस्तकें प्रकाशित। आपके कई उपन्यासों और कहानियों का देश-विदेश की कई भाषाओं में अनुवाद।

सम्मान- हैलमनहैमट ग्रान्ट, ह्यूमन राईट्स वॉच, न्यू यॉर्क, व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, राम मनोहर लोहिया सम्मान (उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान), लाइफटाइम अवॉर्ड, (टाइम्स आफ इंडिया) साहित्यकार सम्मान , हिन्दी अकादेमी दिल्ली, साहित्य भूषण उत्तर (प्रदेश हिन्दी संस्थान), महाराज वीरसिंह पुरस्कार (मध्यप्रदेश साहित्य परिषद), सेठ गोविन्द दास पुरस्कार।

जितेन्द्र भाटिया

जन्म : 1946, (राजस्थान)

शिक्षा-स्कूली शिक्षा के बाद पूरी पढ़ाई आईआईटी बॉम्बे से। केमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी।

प्रकाशित कृतियाँ- उपन्यास- ‘समय सीमान्त’, ‘प्रत्यक्षदर्शी’, ‘जुस्तजू-ए-निहां उर्फ़ रूणियाबास की अन्तर्कथा’। कहानी संग्रह- ‘रक्तजीवी’, ‘शहादतनामा’, ‘सिद्धार्थ का लौटना’, ‘यहां से शहर को देखो’, ‘अगले अँधेरे तक’। नाटक- ‘जंगल में खुलने वाली खिड़की’, ‘रास्ते बन्द हैं’। वे एक प्रमुख स्तंभकार भी रहे हैं। अनुवाद- उन्होंने विश्व साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया है, और ‘सोचो साथ क्या जाएगा’ नामक स्तंभ के माध्यम से पाठकों को विश्व साहित्य से जोड़ा है। उनकी रचनाओं का भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है।

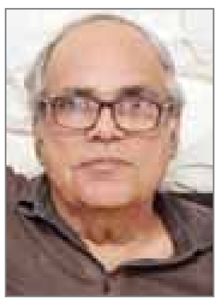

सम्मान- ‘प्रत्यक्षदर्शी’ पुस्तक के मराठी अनुवाद को 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

अलका सरावगी

जन्म: 17 नवंबर 1960 कलकत्ता। कलकत्ता विश्वविद्यालय से हिंदी में पीएचडी।

प्रकाशित कृतियाँ-कहानी संग्रह- कहानी की तलाश में, दूसरी कहानी। उपन्यास-कलिकथा वाया बाइपास’, शेष कादंबरी, कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद, जानकीदास तेजपाल मैन्शन, एक सच्ची झूठी गाथा, कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, गांधी और सरलादेवी: बारह अध्याय, कलकत्ता कॉस्मोपॉलिटनः दिल और दरारें। अनुवादः तेरह हलफ़नामे (विभिन्न भारतीय भाषाओं की लेखिकाओं द्वारा रचित कहानियों का अनुवाद)। आपकी कई रचनाओं और पुस्तकों का भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में अनुवाद।

सम्मान- साहित्य अकादमी पुरस्कार, कलिंगा लिटफ़ेस्ट का ‘बुक ऑफ़ द ईयर अवार्ड’, वैली ऑफ़ वर्ड्ज़, (देहरादून), अंतरराष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा पुरस्कार, केके बिरला फ़ाउंडेशन का बिहारी सम्मान, इटली की सरकार द्वारा ‘ऑर्डर ऑफ़ द स्टार ऑफ़ इटली- कैवेलियर’ सम्मान। दयावती देवी मोदी स्त्री-शक्ति सम्मान, फ़क़ीर मोहन सेनापति सम्मान।

महेश दर्पण

जन्म-1 जुलाई 1956, धर्मशाला (हिमाचल) में।

नव्यतं कहानी संग्रह ‘पड़ाव’ सहित अब तक दस कहानी संग्रह प्रकाशित। लघुकथा संग्रह- मिट्टी की औलाद, हमारा समय, बेमिसाल लघुकथाएँ। उपन्यासः ‘दृश्य-अदृश्य’। आलोचनाः ‘रचना परिवेश’, ‘कहानीः नई पुरानी’, ‘हिंदी कहानी का विकास’, ‘वनमालीः एक कृती व्यक्तित्व’ सहित यात्रावृत्त, साक्षात्कार, जीवनी बाल साहित्य की दस पुस्तकों का लेखन। कथेतर साहित्य की बीस पुस्तकों का संपादन एवं लेखन। विशेष- कहानीः ‘छल’ पर इसी नाम से फिल्म। मास्को विश्वविद्यालय सहित अनेक स्तरों पर रचनाएँ पाठयक्रमों में सम्मिलित।

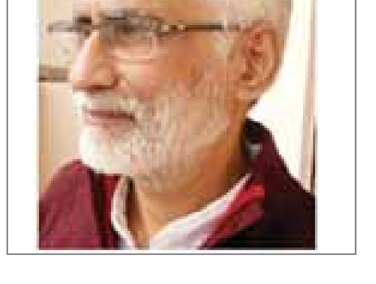

सम्मान एवम पुरस्कार- राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त गणेशशंकर विद्यार्थी सम्मान, पूश्किन सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा साहित्यकार सम्मान एवं कृति सम्मान, स्पंदन आलोचना सम्मान, नई धारा रचना सम्मान, पीपुल्स विक्ट्री अवार्ड, सुभाष चंद्र बोस सम्मान, राजेंद्र यादव सम्मान, दीपशिखा सम्मान सहित अनेक सम्मान एवम पुरस्कार।

उर्मिला शिरीष

जन्म-19 अप्रैल 1959, शिक्षा- एम.ए.,पीएच.डी., डी.लीट्।

प्रकाशित कृतियाँ- कहानी संग्रह- मैं उन्हें नहीं जानती, नानी की डायरी, दस प्रतिनिधि कहानियाँ, ऐ देश पता तुझे हुआ क्या है, नाचगान, उर्मिला शिरीष की लोकप्रिय कहानियाँ, बिवाईयाँ तथा अन्य कहानियाँ, दीवार के पीछे, मेरी प्रिय कथाएँ, ग्यारह लंबी कहानियाँ, कुर्की और अन्य कहानियाँ, लकीर तथा अन्य कहानियाँ, पुनरागमन, निर्वासन, रंगमंच, शहर में अकेली लड़की, सहमा हुआ कल, केंचुली, मुआवजा, वे कौन थे। उपन्यास- खैरियत है हुजूर, चाँद गवाह, ‘कोई एक सपना’ सहित जीवनी, साक्षात्कार, आलोचना, कहानी संकलन की काई पुस्तकों का लेखन-संपादन। आपकी कई कहानियों तथा उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं सहित अंग्रेजी में अनुवाद।

सम्मान- मध्यप्रदेश शासन संस्कृत विभाग का राज्य शिखर सम्मान, अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार, वागीश्वरी पुरस्कार, कमलेश्वर कथा सम्मान, कृष्ण प्रताप कथा सम्मान, विजय वर्मा कथा सम्मान, निर्मल पुरस्कार, भारत सरकार की सीनियर फैलोशिप, धर्मपाल फैलोशिप, कुसुमांजलि फाउंडेशन फैलोशिप। केंद्रीय साहित्य अकादमी, नई दिल्ली की जनरल काउंसिल की सदस्य।

यतीन्द्र मिश्र

जन्म : यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन् 12 मई 1977 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ।

प्रकाशित कृतियाँ-कविता-संग्रह ‘अयोध्या तथा अन्य कविताएँ’, ‘यदा-कदा’, ‘ड्योढ़ी पर आलाप’। शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक ‘गिरिजा’ नामक पुस्तक का लेखन। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का सह-संपादन। कुँवर नारायण पर आधारित दो पुस्तकों और ‘स्पिक मैके’ के लिए संपादन। प्रदर्शनकारी कलाओं पर लिखित निबंधों की किताब ‘विस्मय का बखान’ तथा कन्नड़ शैव कवयित्री अक्क महादेवी के वचनों का हिंदी में पुनर्लेखन ‘भैरवी’ नाम से प्रकाशित। फ़िल्म निर्देशक एवं गीतकार गुलज़ार की कविताओं एवं गीतों के चयन क्रमशः ‘यार जुलाहे’ तथा ‘मीलों से दिन’ नाम से संपादन।

सम्मान-लता मंगेशकर पर ‘लता सुर गाथा’ पुस्तक के लिए 64वाँ राष्ट्रीय पुरस्कार। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार

कुणाल सिंह

जन्म-22 फरवरी 1980 को कोलकाता के समीपवर्ती गाँव में हुआ।

शिक्षा-प्रेसीडेंसी कॉलेज कोलकाता से हिंदी साहित्य में एम.ए. और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से एम.फिल.।

प्रकाशित कृतियाँ- ‘सनातन बाबू का दाम्पत्य’, ‘इतवार नहीं’, ‘अन्य कहानियाँ तथा झूठ’, (कहानी संग्रह); ‘आदिग्राम उपाख्यान’, ‘उत्तरजीवी (उपन्यास); ‘रोमियो जूलियट और अँधेरा’ (लघु उपन्यास)। सभी महत्वपूर्ण भारतीय भाषाओं के साथ-साथ इतावली और जर्मन में उनकी कहानियों के अनुवाद। ‘आखेटक’ कहानी पर फिल्म निर्मित और ‘साइकिल कहानी’ के कई नाट्य-मंचन।

सम्मान- ‘रवींद्र कालिया कथा सम्मान’, ‘साहित्य अकादेमी युवा पुरस्कार’, ‘विजय मोहन सिंह स्मृति युवा कथा सम्मान’, ‘भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार’, भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार’, ‘कथा अवार्ड’, ‘कृष्ण बलदेव वैद फैलोशिप’, पश्चिम बंग राज्य युवा पुरस्कार और ‘नागार्जुन सम्मान’ से सम्मानित।

अंजुम शर्मा

जन्म- 28अगस्त 1989, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश।

शिक्षा- दिल्ली विश्वविद्यालय से सोशल मीडिया से जुड़े विषय पर पीएच.डी.। कवि, संपादक और पत्रकार अंजुम शर्मा हिंदवी की चर्चित साहित्यिक वार्ता-श्रृंखला ‘संगत’ के लिए ख्यात हैं, जिसमें उन्होंने देश के प्रतिष्ठित 100 हिंदी लेखकों के साथ गहन संवाद किए और एक ऐसा आर्काइव तैयार किया जो दुर्लभ है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अतिथि प्राध्यापक रहे अंजुम शर्मा इंडिया टुडे (हिंदी) के डिप्टी एडिटर है और साहित्य से जुड़े विषयों पर डिजिटली सक्रिय हैं। वे आकाशवाणी, दूरदर्शन, बीबीसी हिंदी, आज तक रेडियो से भी संबद्ध रहे हैं जहाँ वे साहित्यिक कार्यक्रमों को जगह देते रहे हैं।

उनकी कविताएँ और लेख प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं।

सम्मान- शब्द शिल्पी सम्मान (झारखंड), स्पंदन युवा पुरस्कार (भोपाल)

कला का आदर्श

कला की उत्पत्ति का कारण है मनुष्य के अन्त:करण का आह्लाद। यह आह्लाद संसार की स्थूलता में, जीवन के स्वार्थों से ऐसा भिंच गया है कि बिल्कुल आंखों की ओट हो पड़ा है। जैसे इसका कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। पर जब कभी क्षीणप्राण, अस्तित्वहीन आह्लाद, सारी संकीर्णता को छिन्न-भिन्न कर, सारे संकोच को दूर हटाकर एकाएक फूट पड़ता है तब कला का जन्म होता है। मनुष्य कोरा मानवीय है, उसका जीवन से सिर्फ स्वार्थ-प्रयोजन का ही सम्बन्ध है, ऐसा कहने से सारी बात समझ में नहीं आती। सारा मतलब हल नहीं होता। मनुष्य इतना सीधा नहीं कि अपने पूर्ण को वह केवल कारण की शुष्क, निराभरण परम्परा में छोड़कर ही निरस्त बैठ जाए। तब उसके तब उसके ह्रदय के रस का क्या प्रयोजन है? नारी और पुरुष में जो आकर्षण है, उसका क्या अर्थ है? बेरोक-टोक नि:सृत होती सुन्दर चाँदनी जो हम पर सुधा की वृष्टि करती है, उसका क्या मतलब है? अलंकारों और आभरणों के लिए वहां जो सदा का आग्रह है उसमें कौन-सा रहस्य है? कहना चाहिए कि इस कार्य कारण की परम्परा को छोड़कर संसार में एक और परम्परा है। वह आनन्द-आह्लाद की परम्परा है। कला इसी परम्परा को जीवन के बीच स्थापित करती है।

तब कला और आनन्द का अटूट सम्बन्ध है। पर यह सम्बन्ध क्यों है, यही देखना है। यह यह आनन्द सर्वत्र तो दृष्टिगोचर नहीं होता। सारी वस्तुएँ जिस रूप में हैं उस रूप में तो आनन्द प्रदान नहीं करतीं। नारी जब यौवन की सीमा में पहुँच जाती है तभी तो वह आकर्षण की वस्तु होती है। तब इस आनन्द के मूल में क्या है? कहेंगे, सौन्दर्या। कला में भी इस सौन्दर्य की अपेक्षा की जाती है।

प्रश्न यह है कि कला में सौन्दर्य का क्या आदर्श है? ह्यूम ने एक जगह कहा है ‘सौंदर्य वस्तुओं में नहीं, मनुष्य के दृष्टिकोण में होता है, जो उन पर विचार करता है। वस्तु का सुन्दर व असुन्दर लगना मनुष्य की रूचि के विकसित होने पर निर्भर है। किसी वस्तु को केवल आंखों से ही नहीं देखा जाता। उसे मन से समझा जाता है। ह्रदय से छुआ जाता है।

अब प्रश्न यह है कि कला में सौन्दर्य का क्या आदर्श है? ह्यूम ने एक जगह कहा है ‘सौंदर्य वस्तुओं में नहीं, मनुष्य के दृष्टिकोण में होता है, जो उन पर विचार करता है। वस्तु का सुन्दर व असुन्दर लगना मनुष्य की रूचि के विकसित होने पर निर्भर है। किसी वस्तु को केवल आंखों से ही नहीं देखा जाता। उसे मन से समझा जाता है। ह्रदय से छुआ जाता है। विवेक से उसका वजन होता है। जब इन सबमें तारतम्य मिलता है, तभी वस्तु के सुन्दर व असुन्दर होने की परख होती है। इसी से मनुष्यता की रुचि जितना पूर्णता-लाभ करती है उसी अनुपात में उसकी सौन्दर्य की धारणा जटिल और परिवर्तित होती जाती है।

कला का सौन्दर्य के लिए निर्माण नहीं होता, वरन् सौन्दर्य एक कसौटी है जिस पर कला की पूर्णता की जाँच होती है। कला का लक्ष्य है हमारे और जगत के बीच आनन्द की सृष्टि करना। इसी से कला में जो कुछ व्यक्त होता है वह बड़ा ही सरस, बड़ा ही मार्मिक और बड़ा ही चमत्कारपूर्ण होता है। कलाकार, अपनी बात से ह्रदय को आविर्भूत करने के केवल कोरे शब्दों का ही सहारा नहीं लेता। वह अपनी बात को नाना प्रकार के आभास-इंगितों से सजाता है। अपनी कलम की विचित्र भंगिमाओंसे उसे बाँका करता है और अपनी प्रतिभा से उसे धो-साफकर एकदम उज्जवलतर, स्पष्टतर कर देता है। इस तरह कला में सौन्दर्य का सृजन होता है।

पर एक बात का हमने अभी तक जवाब नहीं दिया है। प्रश्न है सौन्दर्य से हमें आनन्द क्यों प्राप्त होता है? कह चुके हैं कि कला में अभिव्यक्ति ही अपेक्षित नहीं है,उस अभिव्यक्ति का चमत्कारपूर्ण होना, उसकी मार्मिकता और व्यापकता भी निर्दिष्ट है। यह जगत् कितना विस्तृत है! पर हमारा ह्रदय इसके कितने भाग का अधिकारी है। हमें मालूम है कि गरीब के हमारे जैसे ही सुख दुख हैं। उसे भी पीड़ा-वेदना है। पर क्यों उसके सुख दुख होते हुए भी हमारे लिए असत्य हैं? पर जब यही गरीब की करुण वेदना कला में अवतरित होकर हमारे सन्मुख पहुँचती है तब हम रो पड़ते हैं। स्वयं के दुख से व्यथित हो उठते हैं। यह क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि कला में गरीब की पीड़ा, एक नवीन ध्वनि से भरकर, एक बिलकुल नए आकार में सजकर एकदम अपूर्व-सी लगने लगती है जो ह्रदय को आकर्षित कर, निकट आ एकाएक सत्य हो पड़ती है। एक परायी लड़की को न जाने कितने दूर से हम घर लाते हैं। पर एक दिन वही अपरिचित लड़की, जो हमारे जीवन में पहले कभी नहीं थी, ऐसी सत्य हो जाती है कि उसके सामने हमें अपने घर के बन्धु-बान्धव भी असह्य-से लगने लगते हैं, केवल उसी लड़की के सुख दुख से हमारा सुर मिल पाता है। तब सवाल का जवाब मिलता है कि यह सौंदर्य वस्तुओं को छील- साफ कर, मधुर कर उन्हें रूप-रस-गन्ध प्रदान कर प्राण-रूप में हमारे सन्मुख ला खड़ा करता है और इस तरह उन्हें सत्यता से मण्डित कर हमारे आनन्द का कारण होता है।

तब सत्य और सुन्दर दो अलग पदार्थ नहीं हुए। सत्य ही सुन्दर है और सुन्दर ही सत्य है। पर कला के लिए सत्या क्या वस्तु है, यही देखना है। यह बिल्कुल ही गलत होगा कि कला के लिए प्रकृति ही पूर्ण सत्य है। यह कला केवल प्रकृति की प्रतिकृति है। कहना तो यह चाहिए कि कला प्रकृति है जो मनुष्य की आत्मा द्वारा परिवर्तित की गयी है और नाना रूप से उसका श्रृंगार हुआ है। इसलिए कला के सत्य में आदर्श भी समाविष्ट रहता है। पर सत्य का विवेचन बिना आदर्श से प्रभावित हुए नहीं रहता और कलाकार की प्रतिभा का जादू एक प्रतिलिपिकार वेफ कौशल को बहुत दूर लाँघ आता है। बात यह है कि कला के लिए सत्यता इतनी और किसी बात में नहीं है जितनी कि वस्तु को प्राण लाभ कराने में। यह जो हम जीवन तो दे पाते हैं, पर उसकी आत्मा को नहीं छू पाते हैं, जो हिलता-डुलता प्राणमय पदार्थ प्रतिदिन चल रहा है, इसे तो ह्रदय के भीतर अनुभव करते हैं, पर यह प्रतिदिन चलकर कहाँ केन्द्रीभूत हो रहा है, इसका क्या रहस्य है, इसकी बात हमारी समझ में नहीं आती इन्हीं बातों को सुलझाने के लिए तो कला की संज्ञा दी जाती है। दर्शन भी तो इन्हीं बातों का विवेचन करते हैं। तब भेद क्या है कला में दर्शन की भाँति हमें सत्य की कोरी प्रतिलिपि या तसवीर या विवेचना ही नहीं मिलती। कला को सचमुच सत्य को सुन्दर कर, उसे निकट ला, उसे गौरव से मण्डित करना पड़ता है और उसमें जीवन की प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। दर्शक जब उसवेफ स्पर्श में आता है तब कलाकार का सत्य फिा से, नए सिरे से के ह्रदय में मूर्त लाभ कर लेता है। कलाकार की कला की श्रेष्ठता व निपुणता इसी पुनर्निर्माण में निहित है।

जब हम कहते हैं कि कला इस अपूर्ण अधूरे जीवन को सब ओर से पूर्ण करके समझने का प्रयत्न है। कला के लिए केवल बाह्य लालित्य ही वांछनीय नहीं है, उसे आत्म-मन्थन के प्रसाद की भी आवश्यकता है। अंतर्सौंदर्य के आविर्भाव से ही, सच में, कला की सत्यता है।

सत्य और सुन्दर की ओट में अभी तक किसी वस्तु को हम छोड़ते आए हैं, ऐसा जान पड़ता है। जिस सुर की हमें याचना है, वह अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। भीतर के प्रकाश से जैसे हम बिल्कुल वंचित हैं। नारी के सौंदर्य से हम वशीभूत होते हैं जरूर। पर जी में हरदम एक कलप बनी रहती है कि इस सौन्दर्य की बाह्य सीमा ही न हो। यह अन्तर तक फैला हुआ हो। यह हमारी आकर्षण की ही वस्तु न रहे। यह मर्यादित होकर सामंजस्य को प्राप्त हो।